www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 33 | गोरखपुर, 2 मार्च 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

कर्नाटक सीएम ने परिसीमन के दावों की आलोचना की

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बयान में परिसीमन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, इसे 'विश्वसनीय नहीं' और 'दक्षिणी राज्यों में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से' कहा। सिद्धारमैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दावे का कड़ा विरोध किया कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बयान में कहा, ऐसा लगता है कि या तो उनके पास उचित जानकारी का अभाव है या फिर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर मंशा है।

शाह का दावा - कि परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा- या तो सटीक जानकारी के अभाव से उपजा है या अधिक चिंताजनक रूप से, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को कमतर आंकने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। गुरुवार को उनके कार्यालय द्वारा जारी बयान में उन्होंने गृह मंत्री से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या परिसीमन प्रक्रिया सबसे हालिया जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित होगी या फिर यह लोकसभा सीटों के मौजूदा आवंटन का अनुसरण करेगी।

प्रतिनिधित्व बनाम जनसंख्या नियंत्रण

सिद्धारमैया के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों के विपरीत, दक्षिणी राज्यों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्टता हासिल की है। हालांकि, अगर लोकसभा सीटों का आवंटन हालिया जनगणना डेटा (2021 या 2031) के आधार पर किया जाता है, तो दक्षिण का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा- **अनुमानित सीट नुकसान** (दक्षिण) कर्नाटकः 28 - 26, आंध्र प्रदेशः 42 - 34, केरलः 20 - 12, तमिलनाडुः 39 - 31

अनुमानित सीट लाभ (उत्तर) उत्तर प्रदेशः 80 - 91, बिहारः 40 - 50, मध्य प्रदेशः 29 - 33 ।

बयान में पूछा गयाः परिणामस्वरूप, अगर परिसीमन नवीनतम जनगणना पर आधारित है, तो कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में कमी या स्थिरता देखी जा सकती है, जबकि उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी। किसी भी परिदृश्य में, दक्षिणी राज्यों को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है?

निष्पक्षता की मांग सिद्धारमैया ने केंद्र से आग्रह किया कि या तो 1971 की जनगणना को सीट आवंटन के आधार के रूप में बनाए रखा जाए या दक्षिण के हिस्से को कम होने से रोकने के लिए लोक- सभा सीटों की कुल संख्या में विस्तार किया जाए। उन्होंने मोदी सरकार पर दक्षिणी राज्यों को कमजोर करने के लिए परिसीमन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अनुचित कर नीतियां, जीएसटी आवंटन और आपदा राहत से इनकार। बयान में कहा गया है, हालांकि, परिसीमन के लिए नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा दिखाए गए असाधारण उत्साह को देखते हुए, ऐसा लगता है कि असली इरादा दक्षिणी राज्यों के लोगों को उनकी पार्टी के प्रभुत्व का विरोध करने के लिए दंडित करना है।

सिद्धारमैया ने जनता को कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की चेतावनी की याद दिलाई, जहां उन्होंने राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समर्थन नहीं मिलने की धमकी दी थी, जब तक कि राज्य भाजपा का समर्थन नहीं करता। मुख्यमंत्री ने इस व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने पर भी प्रकाश डाला।

एकता का आह्वान- उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साधने के लिए राज्य से भाजपा और सहयोगी जनता दल (सेक्युलर) के सांसदों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, इन बार-बार हो रहे अन्याय को देखने के बावजूद, कर्नाटक से लोकसभा के लिए चुने गए 17 भाजपा सांसद और 2 जद (एस) सांसद गुलामों की तरह चुप हैं। इस बीच, राज्य में भाजपा के नेता छोटे-मोटे आंतरिक संघर्षों और बदनामी में व्यस्त हैं। सिद्धारमैया ने कन्नड़ लोगों से जाति, धर्म और पार्टी के मतभेदों को अलग रखकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आग्रह किया।

एक रिपोर्ट के अनुसार, परिपत्र में कहा गया है कि इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राज्य के भीतर सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्मित सभी औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों पर अन्य भाषाओं के साथ-साथ कन्नड़ में नाम और उपयोग के निर्देश अनिवार्य रूप से मुद्रित होने चाहिए।

भाषा विवाद के बीच कर्नाटक सरकार का फरमान

बेंगलुरु। कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने और इसके व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, कर्नाटक सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि राज्य में निर्मित सभी औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों को अन्य भाषाओं के साथ-साथ कन्नड़ में अपने नाम और उपयोग निर्देश प्रदर्शित करने होंगे। फरवरी में जारी एक सर्कुलर में सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्देश सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के निमार्ताओं पर लागू होता है। परिपत्र में भूमि की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने में भाषा के महत्व पर जोर दिया गया।

एक रिपोर्ट के अनुसार, परिपत्र में कहा गया है कि इसके द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राज्य के भीतर सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्मित सभी औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों पर अन्य भाषाओं के साथ-साथ कन्नड़ में नाम और उपयोग के निर्देश अनिवार्य रूप से मुद्रित होने चाहिए। इस निर्देश का कार्यान्वयन कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम, 2022 की धारा 9 के तहत नामित अधिकारियों के दायरे में आता है। इन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि सभी निर्माता दिशानिदेर्शों का पालन करें।

इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कन्नड़ को फलने-फूलने के लिए, उत्पादन और विपणन सहित व्यावसायिक गतिविधियों में भाषा को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। कन्नड़ को बढ़ावा देने और कन्नड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करने के लिए, सरकार ने कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम, 2022 लागू किया, जो 12 मार्च, 2024 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 17(7) में कहा गया है कि कर्नाटक के भीतर निर्मित और बेचे जाने वाले सभी उत्पादों के नाम और उपयोग निर्देश, यदि लागू हो, तो किसी भी अन्य भाषा के साथ कन्नड़ में मुद्रित किए जाने चाहिए।

हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्पवर्षा

महाकुम्भ नगर। अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर योगी सरकार ने संगम स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं के अनुभव को यादगार बनाने के लिए उन पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्पवर्षा कराई। पिछले सभी प्रमुख स्नान पर्वों पर सरकार फूलों की वर्षा करा चुकी है। इसी क्रम में बुधवार को महाशिवरात्रि पर भी इस परम्परा का पालन करते हुए 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पवर्षा कराई गई। इसकी शुरूआत सुबह 8 बजे से ही हो गई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न तटों पर स्नान कर रहे थे। आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम, हर हर महादेव, गंगा मइया और तीर्थराज के जयकारे लगाए। अपनी धार्मिक आस्था को सम्मान दिए जाने पर श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

आशा कार्यकताओं के लिए ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश को मिली मंजूरी

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकताओं (आशा) के लिए ग्रेच्युटी एवं सवेतन मातृत्व अवकाश तथा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं को उपदान का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। वे लोग और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं।

जारी की गई एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, इससे 30 वर्ष की सेवा देने वाली प्रत्येक आशा (कार्यकर्ता) को 1.50 लाख रुपये का सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्णय से 42,752 कार्यकताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने पात्र स्वास्थ्यकर्मियों की पहली दो गभार्वास्था के दौरान 180 दिनों के सवेतन मातृत्व अवकाश के विस्तार को मंजूरी दी है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इसके अलावा नायडू ने आशा कार्यकताओं की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है।

अदालत ने दी पुलिस को शेहला रशीद के खिलाफ मामला वापस लेने की अनुमति

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को जेएनयूएसयू की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद शोरा के खिलाफ सेना पर उनके ट्वीट के लिए मामला वापस लेने की अनुमति दे दी है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर उस आवेदन पर 27 फरवरी को यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है।

आवेदन के अनुसार, उपराज्यपाल का आदेश जांच समिति की सिफारिश पर आया है। उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के जरिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों में संलिप्त होने का आरोप था। शेहला रशीद के 18 अगस्त 2019 के ट्वीट में सेना पर कश्मीर में घरों में घुसने और स्थानीय लोगों को यातना देने का आरोप लगाया गया था। सेना ने आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया।

अनुच्छेद 136 में हस्तक्षेप संकीर्ण माना गया, इससे मध्यस्थता प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा : धनखड़

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि विशेष अनुमति याचिका का प्रावधान एक संकीर्ण रास्ता माना जाता था, लेकिन अब इसके व्यापक इस्तेमाल के कारण मध्यस्थता प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा है। धनखड़ ने मध्यस्थता मामलों में विशेषज्ञों की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा कि वाणिज्यिक विवादों से जुड़े जटिल मामलों को निपटाने में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

यहां मध्यस्थता पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने अनुच्छेद 136 के उपयोग एवं मध्यस्थता प्रक्रिया पर इसके प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, ह्यह्यअनुच्छेद-136 के तहत हस्तक्षेप को संकीर्ण माना गया था। कुल मिलाकर इसमें सब शामिल हैं कि मजिस्ट्रेट को क्या करना है, सत्र न्यायाधीश को क्या करना है, जिला न्यायाधीश को क्या करना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या करना है।

संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए ह्यह्यविशेष अनुमति प्रदान करने की अनुमति देता है। इसे विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) कहा जाता है। उन्होंने कहा, ह्यह्यमैं पूरी विनम्रता और इस देश के एक चिंतित नागरिक के रूप में यह सुझाव दे रहा हूं कि जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, वह सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सरल मध्यस्थता प्रक्रिया चाहते हैं।

महिलाओं के आने वाले हैं अच्छे दिन

नई दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं को 8 मार्च तक भाजपा सरकार के वित्तीय सहायता कार्यक्रम के तहत 2,500 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इसका संकेत दिया था। यह पहल, जो भाजपा का एक महत्वपूर्ण अभियान प्रतिज्ञा थी, महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इससे पहले, आप सरकार ने महिला सम्मान योजना शुरू की थी, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को एक हजार रुपए मासिक प्रदान किए जाते थे, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 2,100 रुपए करने की योजना है।

दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग को महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक देने, गर्भवती माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पहल के लिए गुरुवार तक प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा गया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि महिला सम्मान योजना को महिला समृद्धि योजना के रूप में पुनः ब्रांडेड किया जा रहा है, जिसके लाभार्थियों को अब प्रति माह 2,500 रुपए मिलेंगे, जो कि अअढ सरकार द्वारा पहले वितरित किए गए 1,100 रुपए से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

भाजपा सरकार ने सबसे पहले लाडली बहना योजना शुरू की, जिसने राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की। तब से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने इसी तरह की योजनाएं लागू की हैं जो महिलाओं के खातों में सीधे नकद जमा प्रदान करती हैं। 19 फरवरी को भाजपा विधायक दल की नेता चुनी गईं रेखा गुप्ता ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता को प्राथमिकता देने के निरंतर महत्व पर जोर दिया। दिल्ली चुनावों की अगुवाई के दौरान, आप ने अपने प्रमुख वादों में से एक के रूप में 2,100 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करने का वादा किया था।

लालू परिवार ने बिहार को 15 साल में बनाया खटारा, नीतीश ने दिया तेज विकास : सम्राट चौधरी

पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि एक यशस्वी राजनेता को लालू परिवार के गाली देने से उनकी उम्र लंबी हो रही है । वे अभी और 15 साल बिहार की सेवा करते रहेंगे। चौधरी ने कहा कि जैसे 66 करोड़ लोगों को महाकुम्भ आस्था और एकता का सागर दिखा, लेकिन कुछ लोगों को वह फालतू लगा, वैसे ही बिहार में 20 साल में नीतीश सरकार के विकास का शानदार ग्राफ, राजस्व में 15 गुना वृद्धि, 14.5 फीसद की तेज विकास दर और प्रति व्यक्ति आय का 7 हजार बढ़ कर 66 हजार रुपये होना राजद को कबाड़ लग रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 15 साल में बिहार को जर्जर सड़क, अपहरण उद्योग, बिजली-रहित गांव, जातीय हिंसा और 100 से ज्यादा नरसंहार दिये, उनका परिवार आज विकास का चकाचौंध प्रकाश नहीं देख पा रहा है। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के सफल नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग

से बिहार ने गरीबी-अशिक्षा-बेरजगारी और अपराध के अँधेरे से निकाल कर तेज विकास के प्रकाश की ओर जो यात्रा शुरू की है, उसे बार-बार जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में एनडीए 225 सीटें जीत कर लौटेगा। जनता विकास की लय नहीं टूटने देगी।

जीवन में जो रहस्य-दृश्य देखते हैं उसी का नाम विज्ञान: डॉ. मोहन यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विज्ञान के आधार पर व्यवस्थित कार्यप्रणाली, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और नवीनतम तकनीकों के उपयोग ने देश को विश्व के शीर्ष राष्ट्रों में गिने जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। सीएम ने शुक्रवार को विज्ञान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं और तकनीकी का इस्तेमाल कर अपने आविष्कार प्रदर्शित करने वाले युवाओं से सवाल-जवाब किए। प्रतिभा प्रदर्शन करने पहुंचे बच्चों से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व को लेकर सवाल किए। सीएम ने बच्चों को जीवन का अर्थ बताते हुए कहा कि जीवन मिलने के बाद सब कुछ मृत्यु की ओर दौड़ रहा है। इसके लिए अर्जुन-कृष्ण संवाद का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सब कुछ चलायमान है। जीवन तो जन्म के साथ एक ही बार मिला है। हम सब जीवन के बीच जो भी रहस्य और दृश्य देखते हैं उसका नाम विज्ञान है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्टेम एजुकेशन का विज्ञान भवन में शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेंटर में प्रस्तुत मॉडल तथा विद्यार्थियों को विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, सरलता से समझाने में सहायक उपकरणों के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल और नवाचारों के संबंध में उनसे चर्चा की। डॉ. यादव ने टीकमगढ़ से आए प्रगतिशील कृषक पूरनलाल कुशवाहा से भेंट कर उनके द्वारा सिंचाई के लिए विकसित किए गए पवन और पानी से चलने वाले पंप का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री ने फसल बीमा के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम, 13वें मध्यप्रदेश कारीगर विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान मंथन यात्रा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम,

विक्रमोत्सव-2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन और विज्ञान उत्सव तथा पेटेंट और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण व केंद्र स्थापना पर विकसित पोस्टरों का विमोचन किया। डॉ. यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा वीआईटी भोपाल के मध्य अकादमिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पत्रिका ₹रचनाᳫ का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट (सीवी) रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ. यादव ने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत में विकसित खगोल शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों पर विद्यार्थियों से संवाद किया।

महानिदेशक मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद अनिल कोठारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विज्ञान एवं नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य में विज्ञान के प्रति जागरूकता तथा विज्ञान नवाचार में शोध को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन ने विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में स्वर्णिम अध्याय लिखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में जिज्ञासा और विज्ञान के आधार पर व्यवस्थाओं के विकास की प्राचीन परंपरा रही है। पश्चिम में दूरबीन के आविष्कार के पहले से भारत में नवग्रह की पूजा की जाती रही है। भारत ने विश्व में सबसे पहले खगोल विज्ञान के अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। सीएम यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने 'यत पिंडे-तत ब्रह्माण्डे' के माध्यम से सृष्टि और मानव शरीर की एकरूपता का संदेश दिया। इसी प्रकार चरैवेति-चरैवेति में समय की निरंतरता का बोध होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी प्राचीन भारतीय शास्त्रों में निहित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ब्रह्मांड में कई रहस्य बिखरे हुए हैं, इन्हें खोजना और समस्याओं का हल करना ही विज्ञान है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के आधार पर व्यवस्थित कार्यप्रणाली, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और नवीनतम तकनीकों के उपयोग ने देश को विश्व के शीर्ष राष्ट्रों में गिने जाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

संरक्षण के प्रयासों का दिखा असर

देहरादून। राज्य में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों बीच वन्य जंतुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वन विभाग वन्य जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, इसके अलावा वह नए प्रयास भी कर रहा है। इसमें वास स्थलों में सुधार के तहत अवनत वनों को पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश के साथ ही स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के तहत वन कर्मियों की नियुक्ति कर तैनाती की जानी है । राजाजी टाइगर रिजर्व में जल प्रबंधन के लिए पांच साल पहले वेल, वाटर होल्स और वाइल्ड लाइफ मॉडल लागू किया गया। आरट-ीआर के उप निदेशक गर्मी के समय वन्यजीवों के लि, जल उपलब्धता एक चुनौती रही है। वन्यजीव पानी पीने के लिए आबादी क्षेत्रों की तरफ ही चले जाते थे।अधिकाशं क्षेत्र भाबर क्षेत्र तथा पहाडी क्षेत्र में स्थित होने के कारण बोरिंग के माध्यम से जल उपलब्ध कराना भी सम्भव नहीं था। पांच साल पहले राजाजी टाइगर रिजर्व के धौलखंड और चिल्लावाली रेंज में क्षेत्र क्षेत्रीय भौगोलिक तथा भूगर्भीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चार रेंजों में नौ कुओं का निर्माण किया गया। इसमें ग्रेवीटी के माध्यम से 35 वाटर होलों (कृत्रिम जलाशय) को कुओं से जोड़ा गया। इससे जंगल के वास स्थल में सुधार हुआ। वॉटर होल के पास पक्षियों की संख्या बढ़ी है। यहां पर हिरन से लेकर तेंदुओं की खासी संख्या हो गई है। यहां पर तेंदुओं को देखे जाने के मामले में नंबर वन पर पहुंच गया है। भविष्य में राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर, रवासन, चीला रेंज में इसी मॉडल से वन्यजीवों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, अधिकारियों के मुताबिक कार्बेट टाइगर रिजर्व में ऐसी शुरूआत करने की योजना है।

जंगल में बनाए गए खास इको ब्रिज

वन्यजीव संरक्षण का संदेश देने और वन्य जंतुओं के लिए वन विभाग ने कुछ जगह पर इको ब्रिज बनाने का भी फैसला किया। इसमें रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कालाढूंगी - नैनीताल मार्ग पर एक इको ब्रिज बनाया गया, इसी वन प्रभाग के तहत फतेहपुर रेंज में भी बनाया गया था। अब हल्द्वानी वन प्रभाग में भी यह कोशिश की गई है, इसमें हल्द्वानी टनकपुर रोड पर इको ब्रिज बनाया गया है। वन महकमे के अनुसार यह पुल वृक्षवासी बंदर, सरीसृप, गिलहरियों को सड़क दुघर्टना के जोखिम को कम करेगा। इसके अलावा लोगों और पर्यटकों के बीच वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ायेगा।

वनों को बेहतर करने की कोशिश

वन विभाग हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण करता है इसके अलावा वन विभाग में अपने वनों की भी सेहत सुधारने का फैसला किया है। इसमें जिन वनों की स्थिति खराब हुई है वहां आठ साल की कार्य योजना बनाकर उन्हें फिर से पुराने स्वरूप में लाने का काम किया जाएगा। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन कहते हैं कि वास स्थल सुधार समेत अन्य कार्य किए गए हैं।

स्पेशल फोर्स के लिए भर्ती की तैयारी

डेढ़ दशक पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की योजना बनी। इस काम में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में भी मदद की बात की, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते यह फोर्स तैयार नहीं हो सकी। अब वन विभाग नए सिरे से कोशिश कर रहा है इस साल भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। अगर अन्य कोई तकनीकी समस्या नहीं आई तो संभावना है कि इस साल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए वन कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाए। इस फोर्स से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर की सुरक्षा और मजबूत हो सकेगी। इसके अलावा वन विभाग ने हाल के वर्षों में 2155 वन आरक्षियों, 325 वन दरोगा, 46 रेंजर और 45 एसडीओ पदों पर भी भर्ती कर जंगल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाया।

जीआईएस-2025 में 26.61 लाख करोड़ के निवेश करार

17.34 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की भोपाल में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) में दो दिन में 85 एमओयू हुए। इससे 26.61 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव के एमओयू हुए। इससे 17.34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समिट के समापन अवसर पर यह जानकारी दी। समापन सत्र में के-ंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। समिट का शुभारंभ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस समिट से प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

देश और विदेश की नामी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि दो दिन की समिट में 26.61 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं, 17.34 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके पूर्व सरकार की रीजनल इंवेस्टर्स समिट और देश और विदेश में अलग-अलग जगह आयोजित रोड शो में आए निवेश प्रस्तावों को मिला कर कुल 30 लाख 77 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

इन सबको मिलाकर 21 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 2.34 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और 2.74 लाख रोजगार के अवसर और इंटरेक्टिव सेशन में 1.82 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 1.32 लाख रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है।

सक्षम 2024-25 कार्यक्रम का समापन समारोह

छोटे-छोटे प्रयास ऊर्जा संरक्षण में दे सकते हैं अहम योगदान

देहरादून। राज्यस्तरीय समन्वयक के रूप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आईआईपी में सक्षम 2024-25 कार्यक्रम का समापन समारोह गत शुक्रवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में तेल विपणन कंपनियों की ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर अहम भूमिका पर चर्चा की गई।

सूच्य है कि सक्षम के तहत पूरे देश में 14 से 28 फरवरी के बीच वॉकेथॉन, साइकलॉन, समूह चचाएं व एलपीजी पंचायतें आदि गतिविधियां आयोजित हुईं। मुख्य अतिथि अमित कुमार सिन्हा (आईपीएस) ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में किए गए छोटे-छोटे प्रयास भी ऊर्जा संरक्षण में अहम योगदान दे सकते हैं। हेमंत राठौड़ ने तेल विपणन कंपनियों को जागरूकता अभियान चलाने को कहा। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तेल संरक्षण का संदेश दिया गया। वहीं क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान आईआईपी के निदेशक डॉ. हरेंद्र सिंह बिष्ट, वरिष्ठ वैज्ञानिक, विभागाध्यक्ष व दो सौ से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

एक सकारात्मक पहल

समाज की मुख्य धारा से जुडने के इच्छुक कैदी सीख रहे फरार्टेदार अंग्रेजी

इंदौर। इंदौर सेंट्रल जेल में अपराध की दुनिया को पीछे छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की इच्छा रखने वाले 20 कैदी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और फरार्टेदार अंग्रेजी बोलने की कला भी सीख रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह है कि जब वे जेल से बाहर आएं, तो समाज के सामने खुद को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें।

नवाचार से सुधार देखने को मिल रहे

इंदौर की सेंट्रल जेल में वर्तमान में 2000 से अधिक कैदी सजा काट रहे हैं, जिनमें 1455 पुरुष दंडित बंदी, 37 साधारण कैदी, 93 महिला बंदी, 699 विचाराधीन कैदी, 11 मृत्युदंड प्राप्त कैदी, और 16 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध कैदी शामिल हैं। जेल अधीक्षक अलका सोनकर का कहना है कि महिला और पुरुष कैदियों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर नवाचार किए जाते हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप कैदी अब शिक्षा की ओर रुचि दिखा रहे हैं और उन्हें विभिन्न बुनियादी कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आजीवन कारावास की सजा काट रहे परविंदर ने की पहल

जेल के अंदर बनी पाठशाला में हर दिन अंग्रेजी की कक्षाएं लगाई जाती हैं। इन्हीं कक्षाओं में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी परविंदर त्रिलोक सिंह अपने साथी कैदियों को न केवल अंग्रेजी लिखना सिखा रहे हैं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ फरार्टेदार अंग्रेजी बोलने का अभ्यास भी करवा रहे हैं। इस समय जेल की इस पाठशाला में 20 कैदी नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से कई अब धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने लगे हैं। परविंदर त्रिलोक सिंह को वर्ष 2002 में भारतीय दंड संहिता

की धारा 420, 467 और 471 के तहत धोखाधड़ी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और वह 6 दिसंबर 2002 से जेल में सजा काट रहा है। अब उसका संकल्प है कि अधिक से अधिक कैदियों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दिया जाए, ताकि वे जेल से बाहर जाकर समाज में अपनी एक नई और सकारात्मक पहचान बना सकें।

50 कैदी पहली कक्षा से पढ़ाई शुरू कर चुके

जेल प्रशासन द्वारा निरक्षर कैदियों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान में, जेल में 50 से अधिक कैदी पहली कक्षा से अपनी शिक्षा शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कैदी भी हैं, जिनमें से 10 कैदी इस वर्ष इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कैदियों की संख्या 8 है, जो बीकॉम और एमए जैसी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं।

होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी चल रहा

पिछले तीन वर्षों से सेंट्रल जेल में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब तक 10 से अधिक कैदी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से कई कैदी जेल से बाहर जाने के बाद अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, ताकि वे अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छे तरीके से कर सकें।

ऐसे ही एक कैदी, रुस्तम, जो वर्षों पहले हत्या के आरोप में जेल आया था, उसने न केवल उच्च शिक्षा ग्रहण की बल्कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। उसने अपने साथियों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। इसी तरह, जेल में बंद बिरजू अहिरवार ने भी अपने जीवन को बदलने के लिए शिक्षा का सहारा लिया और अब वह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेंट्रल जेल में किए जा रहे ये सुधारात्मक प्रयास कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह पहल न केवल कैदियों के जीवन में बदलाव ला रही है, बल्कि यह समाज में उनके पुनर्वास की संभावनाओं को भी बढ़ा रही है।

कर्नाटक सरकार ने कैंसरकारी इडली बनाने पर कसी नकेल

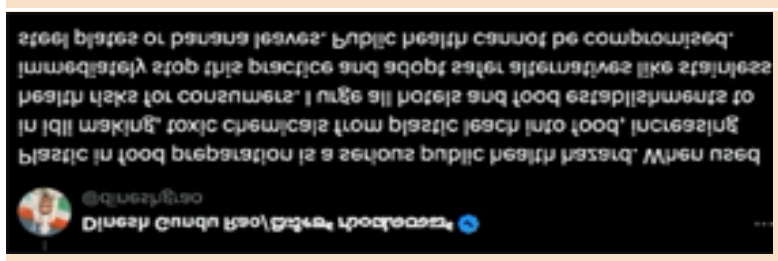

बेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गत गुरुवार को बताया कि कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने पाया है कि राज्य भर में 52 होटल इडली बनाने के लिए पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल कर रहे थे। राव के अनुसार, पॉलीथीन, खासकर पतली शीट का इस्तेमाल, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है क्योंकि यह कैंसरकारी है। नई एजेंसी पीटीआई ने बताया कि राज्य सरकार ने होटल उद्योग में इस तरह की प्रथाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कसम खाई है।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कैंसरकारी तत्वों की मौजूदगी की बात कहने के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी होटलों में इडली बनाने में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गुरुवार को बताया कि कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने पाया कि राज्य भर के 52 होटल इडली बनाने के लिए पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर से इडली के लगभग 250 अलग-अलग नमूनों की जांच की, जिसमें पाया गया कि इडली बनाते समय पारंपरिक कपड़े के बजाय प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गुंडू राव ने मीडिया से कहा, विभाग के अधिकारियों ने राज्य भर से 251 नमूने एकत्र किए और उन्हें जांच के लिए भेजा। पहले इडली बनाते समय कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था, हमें जानकारी मिली कि इन दिनों कुछ जगहों पर कपड़े की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्री ने समझाया इसलिए, हमारे विभाग ने इसकी जांच की। 251 नमूनों में से 52 नमूनों में प्लास्टिक के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक में कार्सिनोजेन्स होते हैं और यह इडली में मिल सकता है। इसलिए, हमारे विभाग ने इसकी जांच की। 251 नमूनों में से 52 नमूनों में प्लास्टिक के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक में कार्सिनोजेन्स होते हैं और यह इडली में मिल सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा न हो और नियम का उल्लंघन करने वाले या प्लास्टिक शीट का उपयोग करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2024 में कर्नाटक सरकार ने खाद्य रंग एजेंट रोडामाइन-बी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका व्यापक रूप से गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी जैसे व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। दिनेश गुंडू राव ने कहा ₹हमने गोभी मंचूरियन डिश पर एक विशेष अभियान चलाया और पाया कि डिश बनाने के लिए हानिकारक रोडामाइन-बी का उपयोग किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक रंग एजेंट है, और हमने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकारी आदेश का पालन न करने पर सात साल या आजीवन कारावास हो सकता है, और ₹10 लाख तक का जुमार्ना भी लगाया जाएगा।

मोबाइल की लत से अभिभावक परेशान

पडरौना। बच्चों की मोबाइल की लत से अभिभावक उनकी सेहत को लेकर परेशान हैं। हालत यह है कि चार से 10 साल तक के बच्चे दो से तीन घंटे मोबाइल चला रहे हैं। इससे अधिकतर बच्चों में दूर दृष्टि दोष की समस्या हो रही है। इसकी वजह से बच्चों के छोटे उम्र में ही मोटा चश्मा लगा रहा है। पुरुष एवं नेत्र चिकित्सालय में हर रोज 10 से 15 बच्चे आंखों की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। बीते शुक्रवार को नेत्र रोग विशेषज्ञ व सर्जन डॉ. ए आलम ने बताया कि सर्दी कम होने के बाद भी हर दिन 100 से अधिक मरीजों की ओपीडी हो रही है। इसमें 10 से 15 बच्चों में आंखों की समस्या आ रही है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चों के खेलने की जगह अधिकतर समय मोबाइल व टीवी से चिपका रहना, इसका बड़ा कारण है। अभिभावकों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस ओर समय से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बच्चों में आंखों संबंधी समस्या बढ़ने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सप्त दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन

सशक्त महिलाएं समाज को दे सकती हैं मजबूती

बस्ती। पंडित महादेव शुक्ल कृषक पीजी कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवायोजना इकाई सावित्री बाई फुले इकाई के सप्त दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन शुक्रवार को नारी सम्मान व महिला सशक्तीकरण पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। शिविर के समापन पर मुख्य अतिथि विद्या देवी बालिका लघु माध्यमिक विद्यालय परास डीह की प्रधानाचार्य कलावती शुक्ला ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सशक्त महिलाएं ही समाज को मजबूती दे सकती हैं। जिस तरह से पिछले सात दिनों से छात्राओं ने सामाजिक मुद्दे को लेकर अलग-अलग दिशाओं में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है, यही असली महिला सशक्तीकरण है। बीडीओ गौर केके सिंह ने कहा कि नारी को सम्मान सृजन और शक्ति का प्रतीक माना गया है।

नारी को कोमलता, क्षमाशीलता और सहनशीलता की मूर्ति माना जाता है। शिविर में स्वयंसेविका सजीना खातून और नित्या ने रंगोली के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया। प्राचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संचालन डॉ. गजेंद्र ऊबारन गिरी ने किया।

पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का काम पूरा, शीघ्र होगा लोकार्पण

गोरखपुर (जीकेबी)। नगर निगम परिसर में मौजूद 100 साल पुरानी लाइब्रेरी के जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो गया है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। लाइब्रेरी में फर्नीचर लग गए हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका लोकार्पण कराने की तैयारी है। सौ वर्ष पुरानी इस लाइब्रेरी को होम्स क्लेन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 1925 में हुई थी। इसे अमन-ओ-अमन सभा के कार्यकारिणी सदस्यों ने शहर के बुद्धिजीवियों के लिए स्थापित किया था। शुरूआत में होम्स क्लेन अमन-ओ-अमन पुस्तकालय कहा जाता था लेकिन बाद में नगर निगम ने इसका नाम बदलकर राहुल सांस्कृत्यायन पुस्तकालय कर दिया। लाइब्रेरी में करीब 15 हजार पुस्तकें मौजूद हैं जिसमें कुछ किताबें ऐसी हैं, जो आज किसी भी दूसरी लाइब्रेरी में मिलनी मुश्किल है।

निगम 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इस लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार करवा रहा है। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने बताया कि लाइब्रेरी में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वाईफाई और कंप्यूटर की सुविधा रहेगी। बैठकर पढ़ने के लिए स्टडी डेस्क, ऑनलाइन पठन सामग्री के लिए फोटोकॉपी करने के लिए प्रिंटिंग जोन और सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगा जा रहे हैं।

धारा-163 जनपद में 15 अप्रैल तक रहेगी लागू

झांसी। होली, ईद-उल-फितर, रमजान का अंतिम शुक्रवार, रामनवमी, महावीर जयंती और डॉ भीमराव आंबेडकर का जन्म दिवस आयोजित होगा। साथ ही विभिन्न सामायिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आयोजित होना है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा। जुलूस नहीं निकालेगा। किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कड़ी सुरक्षा के बीच माशिप की परीक्षा

हाईस्कूल के 1325 परीक्षार्थियों ने छोड़ा गणित का पेपर

इटावा। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को कराई गई। पहली पाली में हाईस्कूल के गणित एवं इंटरमीडिएट के व्यावसायिक शिक्षा का पेपर हुआ। दूसरी पाली में हाईस्कूल के वाणिज्य एवं इंटर के नागरिक शास्त्र विषय के प्रश्नपत्रों की परीक्षा हुई। पहली पाली में 69 एवं द्वितीय पाली में 64 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। पहली पाली में हाईस्कूल में 18136 पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष 16811 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 1325 परीक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा छोड़ दी। इसी प्रकार दूसरी पाली में 2894 पंजीकृत परीक्षार्थियों के सापेक्ष 2740 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 2740 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। दोनों पालियों में कुल 1479 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा से पूर्व सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की तलाशी ली गई। राज्य पर्यवेक्षक राजू राणा की ओर से राममनोहर लोहिया कालेज धनुंआ, मुलायम सिंह यादव इंटर कॉलेज रायनगर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जसवंतनगर का निरीक्षण किया गया। वहीं डीआईओएस मनोज कुमार, सचल दल प्रभारी धमेंद्र कुमार, नीता कटारिया, पूरन सिंह पाल ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।

कियास्क संख्या-दो को अनाधिकृत कब्जे से जीड़ीए टीम ने कराया मुक्त

गोरखपुर (जीकेबी)। गौतम बुद्ध द्वारा पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए गए कियास्क नंबर दो बर किया गया अनाधिकृत कब्जा हटा दिया गया। इसके बाद जीड़ीए की टीम ने नौका विहार पर सड़क किनारे सेल्फी प्वाइंट व टाय ट्रेन के आसपास अनाधिकृत रूप से दुकान लगाने वालों को हटाया गया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के निर्देश पर जीड़ीए की टीम गत शुक्रवार को मौके पर पहुंची। टीम ने पैड़लेगंज स्थित गौतम बुद्ध द्वारके पास कियास्क संख्या-दो को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद टीम रामगढ़ताल स्थित नौका बिहार के प्रवेश द्वार पर ठेला लगाने वालों को खदेड़ा। सेल्फी प्वाइंट- टाय ट्रेन के आसपास अनाधिकृततौर पर वेंडिंग करने वालों को भी हटाया गया। बतादें कि माइकिंग कर अनाधिकृत रूप से दुकान न लगाने की चेतावनी दी गई।

युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार संकल्पित

पडरौना। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार नीति योजना के तहत बृहस्पतिवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पडरौना सभागार में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें युवाओं को ग्रामोद्योग की तरफ से विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि पडरौना चेयरमैन विनय जायसवाल ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। इसके लिए विभिन्न तरह का प्रशिक्षण देकर युवाओं को प्रशिक्षित कर रही। प्रशिक्षित युवा मिले प्रमाण पत्र पर बैंकों से कम ब्याज पर ऋण लेकर अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। जागरूकता शिविर को अपर आयुक्त जिला उद्योग शिवशंकर ने विभाग की तरफ से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर को पंकज पांडेय, राकेश मणि त्रिपाठी आदि ने संबोधित किया।

लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का नया आयाम

वाराणसी। सर सुंदरलाल अस्पताल बीएचयू की जनरल सर्जरी ओटी में एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। बीते 14 फरवरी को विभाग में कोलिडोकल सिस्ट बीमारी का दूरबीन विधि से सफल ऑपरेशन हुआ। बताते चला जाए कि जौनपुर जिले के रामपुर तियारा गांव की 16 वर्षीय शिवानी, अशोक कुमार उपाध्याय की पुत्री पिछले छह वर्षों से पेट दर्द से पीड़ित थी। इस दुर्लभ बीमारी से ग्रसित मरीज की पित्त की नली फूल जाती है और बार-बार पेट दर्द होता है। यह एक लाख बच्चों में से किसी एक को होती है। सर्जरी विभाग की प्रो. मुमताज अंसारी की यूनिट में शिवानी को भर्ती कराया गया। 14 फरवरी को, प्रो. विवेक श्रीवास्तव ने लैप्रोस्कोपिक (दूरबीन) विधि से ऑपरेशन किया। प्रो. अंसारी ने बताया कि जनरल सर्जरी विभाग में यह इस तरह की पहली सर्जरी है, हालांकि विभाग में ओपन (चीरा लगाकर) सर्जरी काफी समय से होती रही है। प्रो. विवेक ने बताया कि लगभग सात घंटे तक चले ऑपरेशन में मरीज की रिकवरी चीरे वाले ऑपरेशन से जल्दी हुई। मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गई है। ऑपरेशन में डॉ. अरविंद प्रताप, डॉ. राजेंद्र, डॉ. श्वेता और डॉ. अनन्य ने सहयोग किया। एनेस्थीसिया प्रो. अनिल पासवान और उनके सहयोगी डॉ. अभय और डॉ. उर्वशी ने दिया। सर्जरी ओटी से नर्सिंग ऑफिसर अनुपमा और दिनेश ने भी ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) कानून 1956 के नियम आठ के अन्तर्गत घूँघट की बगावत, हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र से सम्बन्धित स्वामित्व और अन्य बातों का ब्योरा

प्रारूप-4

1. प्रकाशन स्थल	:	गोरखपुर।
2. प्रकाशन की अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम (क्या भारत का नागरिक है) (यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	पंकज धर द्विवेदी हॉ (भारतीय)
पता-	:	45, बादशाहबाग जगन्नाथपुर, गोरखपुर
4. प्रकाशक का नाम (क्या भारत का नागरिक है) (यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	पंकज धर द्विवेदी हॉ (भारतीय)
पता-	:	45, बादशाहबाग जगन्नाथपुर, गोरखपुर
5. सम्पादक का नाम (क्या भारत का नागरिक है) (यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	पंकज धर द्विवेदी हॉ (भारतीय)
पता-	:	45, बादशाहबाग जगन्नाथपुर, गोरखपुर
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों ।	:	नहीं

मैं पंकज धर द्विवेदी एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

पंकज धर द्विवेदी
(प्रकाशक)

दिनांक 01.03.2025

भारतीय भाषा पुस्तक योजनान्तर्गत दी.द.उ. गो.विवि. 31 पुस्तकें करेगा प्रकाशित

गोरखपुर (जीकेबी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की भारतीय भाषा पुस्तक योजनान्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 14 विषयों की 31 पुस्तकें प्रकाशित करेगा। इनमें 27 मौलिक पुस्तकें होंगी और शेष चार अनूदित होंगी।

सूच्य है कि इस वर्ष केंद्रीय बजट में भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरूआत की गई है जो भारतीय भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की एक पहल है। यह योजना शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़क्षवा देने और भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट पुस्तकों की कमी दूर के उद्देश्य से लागू की गयी है। इससे मातृभाषा में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को भी काफी लाभ होगा। केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद गत सप्ताह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से 25 फरवरी तक इस बारे में एक निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव आमंत्रित किया था। इसमें मौलिक लेखन तथा अनुवाद दोनों श्रेणियों में प्रस्ताव मांगे गए थे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा कुल 31 पुस्तकों के सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें सामाजिक एवं मानविकी संकाय स14, विज्ञान संकाय से 9, वाणिज्य से दो तथा अभियांत्रिकी संकाय से हिंदी भाषा में दो पुस्तकों के लेखन के प्रस्ताव हैं। इसके अतिरिक्त कला संकाय से तीन तथा विज्ञान संकाय से एक पुस्तक के अनुवाद का प्रस्ताव भी दिया गया है।

देश भर से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण के बाद इस वर्ष के अंत तक चयनित पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी जिसे शिक्षा मंत्रालय सहयोग प्रदान करेगा। इस सम्बन्ध में कुलपति प्रो. पूनम टंड़न ने कहा कि मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रस्तावित इस योजना में 31 पुस्तकों के सृजन का प्रस्ताव हमारे शिक्षकों की विद्वता और क्षमता का द्योतक है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढक्षेगी और विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे।

महिला जनसुनवाई कार्यक्रम राज्य महिला आयोग की उपध्यक्ष ने सुनीं उनकी समस्याएं

गोरखपुर (जीकेबी)। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारु चौधरी की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न से संबंधित महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पीड़ितों की फरियाद को गंभीरतापूर्वक सुनें तथा उनका नियमानुसार त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप किसी भी पीड़िता को अनावश्यक परेशान न करें। उपाध्यक्ष ने संबंधित विभागों को प्रकरणों के निस्तारण की अद्यतन आख्या आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कुल 14 प्रकरण आए जिसमें से अधिकांशतः मामले घरेलू हिंसा,दहेज उत्पीड़न गुमशुदगी, जमीनी विवाद, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन,भरण पोषण आदि के रहे। उन्होंने सभी मामलों को गंभीरता पूर्वक सुनने के पश्चात संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पीडिक्षताओं को न्याय तत्काल प्रभाव से मिले। इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही-शिथिलता न बरती जाए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे यह हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड का लाभ सभी पात्र व्यक्ति को अवश्य मिले यह सुनिश्चित करे

सपत्नीक पूजा-अर्चना करते हिमांचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल

नगर निगम का सख्त रूख, 22 दुकानें सील

- दुकानों को जमींदोज कर नगर निगम नए सिरे से दुकानों का निर्माण
- दुकानों का निर्माण दो दशक पहले हुआ था

गोरखपुर (जीकेबी)। स्वयं की जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम ने गत गुरुवार को सख्त रूख अपनाते हुए तुर्कमानपुर स्थित कब्रिस्तान के पास की जमीन पर बनी 22 दुकानों को सील कर दिया। इन दुकानों को जमींदोज कर नगर निगम नए सिरे से दुकानों का निर्माण कराएगा।

जानकार सूत्रानुसार, तुर्कमानपुर कब्रिस्तान के पास कब्रिस्तान का संचालन करने वाली समिति ने 22 दुकानें बना रखी हैं। इन दुकानों का निर्माण दो दशक पहले हुआ था। जमीन की जांच में यह म्यूनिसिपल बोर्ड.के नाम दर्ज मिली।

दुकानदारों ने अपने कब्जे को लेकर कोई साक्ष्य नहीं दिया। इसके बाद संबंधित दुकानदारों को नोटिस देकर सात दिन में दुकानों को खाली करने को कहा गया था। गुरुवार को नगर निगम प्रवर्तन दल, राजस्व और पुलिस की मौजूदगी में दुकानों को सील करने की कार्यवाही हुई। नगर निगम अमले को देखते हुए अधिकतर दुकानदारों ने तुरंत दुकान खाली कर दी। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के मुताबिक तुर्कमानपुर कब्रिस्तान से सटी 22 दुकानें नगर निगम की जमीन पर बनी हैं। इसको लेकर दुकानदारों को नोटिस दी गई थी। जिन्हें बीते दिनों सील कर दिया गया।

मोबाइल कल्चर ने बच्चों और माता-पिता में बढ़ाई दूरियां

बस्ती। सोमवार की रात 12वीं के छात्र आदर्श पांडेय का फंदे से लटका हुआ शव बैरिहवा स्थित प्राइवेट हास्टल में उसके कमरे में मिला। इस घटना ने अभिभावकों को झकझोर दिया है। आदर्श के मित्रों और पड़ोसियों के मुताबिक उसका फिजिक्स का पेपर खराब हो गया था, तभी से वह निराश था। घटना के संबंध में शिक्षाविद्, मनोचिकित्सक, अभिभावकों की राय है कि पढ़ाई को लेकर बच्चों पर अधिक दबाव न बनाएं।

अपेक्षित परिणाम न आने पर दबाव व तनाव की वजह से युवा विद्यार्थी में खुद को खत्म करने का ख्याल आता है। बच्चों से बात करें और उनकी समस्याएं सुनें।

दबाव से अवसाद के शिकार हो रहे युवा

जिला अस्पताल के मनो चिकित्सक डॉ. एके दूबे बताते हैं कि अभिभावक बच्चों की प्रतिभा और उसकी क्षमता को जाने बिना ज्यादा दबाव बनाने लगते हैं। इससे युवा तनाव में आकर अवसाद के शिकार हो रहे हैं। दूसरे मोबाइल कल्चर ने बच्चों और माता-पिता के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। बच्चों से बात न होने से हम उन्हें समझ नहीं पाते।

बच्चों को उचित परामर्श जरूरी

मनोविज्ञान के शिक्षक डॉ. राजेंद्र बौध का कहना है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने और उसके सापेक्ष परिणाम न आने की वजह युवा कुंठा के शिकार हो

रहे हैं। तनाव के कारण वह आत्महत्या की तरफ उत्सुक हो जाते हैं। उचित काउंसिलिंग और परामर्श ये ये भावनाएं कम की जा सकती हैं।

परीक्षा में तनाव न लें बच्चे

अभिभावक ज्योत्सना सिंह का कहना हे कि बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव नहीं लेना चाहिए। जिंदगी में आगे भी परीक्षा देना है। पेपर अच्छे होंगे। उन्होंने कहा कि पेपर बच्चों के स्तर का होना चाहिए। आईआईटी और नीट के स्तर का नहीं।

पेपर बच्चों के स्तर का होना चाहिए

राजकीय इंटर कॉलेज के जीव विज्ञान के शिक्षक डॉ. विवेक मणि त्रिपाठी का कहना है कि बच्चे का दोष नहीं, बल्कि पेपर बनाने वाले का दोष है। प्रश्नपत्र तीन स्तर के बनते है पहला सबसे सरल, थोड़ा कठिन, तीसरा कठिन। पेपर ऐसा होना चाहिए कि कमजोर विद्यार्थी भी हल कर लें और जो तेज विद्यार्थी को कुछ प्रश्न कठिन लगे।

ये लक्षण दिखे तो हो जाएं सतर्क

बच्चा अत्म हत्या करने जैसी बात करे, या धमकी दे। उदास, चिंतित और अवसादग्रास्त दिखाई दे। ज्यादा समय अकेले रहे। अपने में खोया रहे तो अभिभावक को चाहिए कि वह बच्चों से बात करे और उनकी समस्याओं को सुने। जरूरत पड़ने पर काउंसर के पास भी लेकर जाएं।

घूँघट की बगावत
2 मार्च 2025
प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

कामुकता को स्वछन्द करती पॉप संस्कृति

आजकल, हमारी इच्छाएँ और धारणाएँ अक्सर फिल्मों और टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली छवियों और कथाओं से प्रभावित होती हैं। ये चित्रण प्रायः रूढ़िवादिता की ओर अधिक झुके होते हैं। उदाहरण के लिए, पारंपरिक रूप से आकर्षक महिलाओं पर जोर देने से लड़कियों और महिलाओं में उन जैसा दिखने की भावना पैदा हो सकती है। पॉप संस्कृति के उपभोक्ताओं के रूप में, हमारे लिए इसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखना आवश्यक है। हमारे तेजी से विकसित होते समाज में, पॉप संस्कृति हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन गई है। फिल्मों, संगीत, टीवी कार्यक्रमों और सोशल मीडिया का प्रभाव लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़ियों के बारे में हमारे विचारों को महत्त्वपूर्ण रूप से आकार दे सकता है। इसके अतिरिक्त, मीडिया अक्सर सुंदरता के संकीर्ण मानकों को बढ़ावा देता है, तथा पतले शरीर और गोरी त्वचा को तरजीह देता है। यह बात गोरेपन की क्रीम के विज्ञापनों के प्रचलन और बॉलीवुड में गोरी त्वचा वाली अभिनेत्रियों को प्राथमिकता दिए जाने से स्पष्ट है, जो रंगभेद को बढ़ावा देता है।

महिलाओं को समाज के हर पहलू में पूर्णतः और समान रूप से भाग लेने का मौलिक अधिकार है। फिर भी, कार्यस्थल, मनोरंजन और राजनीति जैसे क्षेत्रों में, वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। समय के साथ इस लैंगिक असमानता से प्रगति की धीमी गति का पता चलता है। पितृसत्तात्मक मानदंडों और परंपराओं का प्रभाव व्यापक और हानिकारक है, जो महिलाओं और लड़कियों के साथ-साथ उनके परिवारों और समुदायों के व्यक्तिगत, वित्तीय और भविष्य की भलाई को प्रभावित करता है। भारत में, पॉप संस्कृति और मनोरंजन मीडिया का प्रभाव लैंगिक मानदंडों और सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही धारणाओं, व्यवहारों और कानूनी चर्चाओं को प्रभावित करता है। हालांकि ये माध्यम सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये रूढ़िवादिता को भी कायम रखते हैं। हमारी तेजी से विकसित होती दुनिया में, पॉप संस्कृति हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। फिल्में, संगीत, टेलीविजन कार्यक्रम और सोशल मीडिया हमारी विश्वदृष्टि और अपेक्षाओं को आकार देते हैं। विशेष रूप से लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़ियों के सम्बंध में- जैसे कि यह धारणा कि लड़कियों को गुड़ियों से खेलना चाहिए, जबकि लड़कों को कारों से खेलना चाहिए।

पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर समाज के विचार मीडिया से काफी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, बॉलीवुड की फिल्म कबीर सिंह (2019) में मर्दानगी का एक ऐसा संस्करण दिखाया गया, जिसमें पुरुषों के आक्रामक और हावी व्यवहार का महिमामंडन किया गया। इसी प्रकार, मीडिया में पेशेवर भूमिकाओं का चित्रण कैरियर की आकांक्षाओं को आकार देता है। फिल्म कारगिल गर्ल (2020) ने लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव पर प्रकाश डालते हुए सेना में महिलाओं की भर्ती को प्रोत्साहित किया। मनोरंजन मीडिया अक्सर लैंगिक न्याय पर राष्ट्रीय चर्चा को बढ़ावा देता है, जैसा कि सत्यमेव जयते कार्यक्रम में देखा गया। जो घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों को

सामने लाया। लम्बे समय से चल रहे टेलीविजन धारावाहिक भी पारिवारिक लैंगिक भूमिकाओं को स्थापित करते हैं, तथा भारतीय धारावाहिकों में आमतौर पर देखी जाने वाली आज्ञाकारी बहू की रूढ़िबद्ध छवि को कायम रखते हैं। जनांदोलनों और सक्रियता के बीच सम्बंध को अक्सर मीडिया प्रतिनिधित्व द्वारा सुगम बनाया जाता है। फिल्म छपाक (2020) ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के संघर्षों पर प्रकाश डाला और आईपीसी के तहत सख्त दंड सहित कानूनी सुधारों की वकालत की। यद्यपि लोकप्रिय संस्कृति ने भेदभावपूर्ण लैंगिक मानदंडों को सुदृढ़ करने में भूमिका निभाई है। इसमें उन्हें चुनौती देने और बदलने की शक्ति भी है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है द मार्वलस मिसेज। मैसेल, 1950 और 1960 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें गृहिणी मिरियम मैसेल को स्टैंड-अप कॉमेडी में अपनी प्रतिभा का पता चलता है। इस शृंखला को न केवल आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, बल्कि इसमें महिला सशक्तिकरण, सपनों की खोज और ₹आदर्श₹ गृहिणी की सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्ति जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को भी उठाया गया। यह लोकप्रिय संस्कृति में अनेक उदाहरणों में से एक है।

संगीत और फिल्में प्रायः प्रेम को नियंत्रित और अधिकारपूर्ण दृष्टिकोण से चित्रित करती हैं। कुछ बॉलीवुड गाने जुनूनी पुरुष प्रेमी की छवि को कायम रखते हैं। एक्शन फिल्मों में अक्सर आक्रामक, प्रभावशाली पुरुषों को रोल मॉडल के रूप में दिखाया जाता है। हाल ही में प्रदर्शित फिल्मों में हिंसक और सत्तावादी पुरुष नायकों को प्रमुखता से दिखाया गया है। महिलाओं को आमतौर पर पालन-पोषण करने वाली भूमिकाओं में दिखाया जाता है, जबकि पुरुषों को अधिकार वाले पदों पर रखा जाता है। हालाँकि, फिल्म तुम्हारी सुलु (2017) ने अपरंपरागत करियर में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रदर्शित करके इन मानदंडों को चुनौती दी। मीडिया अक्सर सुंदरता के आदर्श के रूप में पतलेपन और गोरी त्वचा को बढ़ावा देता है, गोरापन लाने वाली क्रीम के विज्ञापन प्रचलित हैं, जो बॉलीवुड में गोरी त्वचा वाली अभिनेत्रियों के प्रति वरीयता और रंगभेद को बढ़ावा देने को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, समलैंगिक पात्रों को अक्सर हास्य के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, तथा कुछ फिल्में व्यंग्यात्मक चित्रण के माध्यम से समलैंगिक आकर्षण को महत्त्वहीन बना देती हैं। हालांकि मनोरंजन मीडिया ने सामाजिक मुद्दों को आगे बढ़ाने और लैंगिक जागरूकता बढ़ाने में भूमिका निभाई है, लेकिन यह हानिकारक आख्यानों को भी बढ़ावा देता है। भविष्य में सार्थक सामाजिक परिवर्तन के लिए, लिंग-संवेदनशील प्रतिनिधित्व, विविध चित्रण और ज़िम्मेदार कहानी कहने पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, लैंगिक समानता और सामाजिक मानदंडों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती है। फिल्में, टेलीविजन, विज्ञापन और सोशल मीडिया या तो उन रूढ़ियों को मजबूत कर सकते हैं जो महिला सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं या फिर सकारात्मक बदलाव के लिए शक्तिशाली एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं।

डा.सत्यवान सौरभ

विपक्ष की राजनीति छीन लेगी महाकुंभ की सफलता

देश में कुछ नेताओं के लिए हिंदू एकता , सनातन पर कुंभ का प्रयोग , प्रयागराज का महाकुंभ नासूर बन कर उभरा है । ममता ने जहां इसे मृत्यकुंभ कहा तो इशारों - इशारों में अखिलेश ने लाशों का खेल और खड़गे ने नौटंकी कह कर देश के राजनैतिक सिनेरियो को भाजपा के पक्ष में मोड़ दिया जिसका लाभ दिल्ली चुनाव में भाजपा को मिला भी और अब काफी हद तक ये बयान इन नेताओं को सत्ता से लंबे समय तक बेदखल कर इनकी राजनीति बदल सकता है । कुंभ का आध्यात्मिक पक्ष अलग बात है और उसकी समग्रता का राजनैतिक लाभ अलग विषय । क्या कुंभ में उमड़े बेशुमार हिन्दुत्व ने एक राजनैतिक दल को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है ! क्या 45 दिनों तक कुंभ की निरन्तर आलोचना ने कई दलों का लोकप्रियता ग्राफ एकदम नीचे गिरा दिया है ? यह प्रश्न हर कोई पूछ रहा और इसका उत्तर आपको मैं अपने इस लेख के माध्यम से दूंगा जिस आप यू समझिए कि बोल तोल मोल के बोल । शब्दों का असर तीर से पैना है , ऐसा घाव कर जाता है जो कभी भरता नहीं । फिर ये घाव तो आस्था पर लगाए गए हैं । जहां तक मौनी अमावस्या पर हुई दुर्घटना का सवाल है , वह दुःखद थी पर ऐसा पहले भी होता आया है और अखिलेश के द्वारा फैलाए गए झूठ का जवाब हिंदुओं ने यूपी में उनसे मिल्कीपुर छीन कर दिया । अनेक कुंभ मेलों पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती आई हैं किंतु किसी ने जहर नहीं बोला जैसा इन नेताओं ने खुलेआम बोला । ऐसी दुर्घटनाएं अलग अलग दलों के शासन काल में ही हैं । यह काफी दुःखद हैं पर बेहद भारी भीड़ के आगे सब विवश हैं । कुंभ के आयोजन के खिलाफ सर्वाधिक बवाल अखिलेश यादव ने मचाया । उनके बाद लालू , खड़गे और ममता रहे । अब वामपंथी दल तो रहे नहीं अतः वामपंथियों का दायित्व भी ममता , खड़गे,अखिलेश और राहुल के कंधों पर आ गया है । यह जानना दिलचस्प हो गया है कि कुंभ से विपक्षी दलों ने कुछ खोया है या पाया है ? एक और बात । क्या बेहद शानदार कुंभ संपन्न कराकर योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2027 को लॉक कर दिया है ! 2029 लोकसभा चुनाव से पहले अभी हरिद्वार अर्द्धकुंभ तथा नासिक और उज्जैन के पूर्णकुंभ होने बाकी हैं । यह जानना और भी दिलचस्प होगा कि भाजपा शासित राज्यों में मिलने वाले ये तीन अवसर क्या 2029 में मोदी के विकल्प को भी लॉक कर देंगे ? मतलब मोदी के पास यदि आगे अवसर नहीं होगा तो क्या शाह शिवराज या योगी को ? बहरहाल राम मंदिर के बाद यह तो पक्का हो गया है विराट हिन्दुत्व का विराट जागरण हो चुका है । इसे रोकना विपक्ष के घटिया पैंतरों के रास्ते मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है । समझिए कि जनता क्या चाहती है ? किसी को गलियां देकर आगे बढ़ने का जमाना अब बीत चुका है । एक और सवाल इन दिनों मीडिया में पूछा जा रहा और चर्चित हुआ है । क्या लालू , अखिलेश , खड़गे और ममता की पार्टियों के हिन्दू कार्यकर्ता अपने नेताओं के बयानों से सख़्त नाराज हैं ? इन दिनों मृत्युकुंभ , गिद्ध और सूअर जैसे शब्दों पर राजनीति गर्म है । कुंभ में देश के 115 करोड़ हिंदुओं में से यदि 66 करोड़ हिन्दू 45 दिनों के महापर्व में बिन बुलावे पहुंच जाते हैं तो तब क्या होगा जब चुनावी समय आने पर वे नेताओं को उनके बयानों की याद दिलाएंगे । उधर पीएम के दौड़ में सबसे आगे मुख्यमंत्री योगी ने बताया है कि महाकुम्भ के कारण यूपी की राज्य जीडीपी में 3 लाख करोड़ (लगभग 35 बिलियन डॉलर) रुपये की वृद्धि होने की आशा है। इस समय यूपी की जीडीपी 26 - 27 लाख करोड़ रुपये है। अर्थात महाकुम्भ का यूपी की जीडीपी में योगदान लगभग 11 से 12 प्रतिशत बैठेगा। अगर भारत के सन्दर्भ में देखें तो राष्ट्र की जीडीपी में महाकुम्भ का योगदान लगभग 1% निकलेगा।अमेरिका की कलाकार एवं सिंगर, टेलर स्विफ्ट, के लिए कहा जाता है कि जिस शहर में वह परफॉर्म करती हैं उस शहर में कुछ समय के लिए मंहगाई लगभग 10 प्रतिशत बढ़ जाती है क्योंकि होटल एवं रेस्टोरेंट फुल एवं मंहगे हो जाते हैं, पर्यटन एवं शॉपिंग बढ़ जाती है। ब्रिटेन में स्विफ्ट के 8 कंसर्ट या परफॉरमेंस ने अनुमानतः 1 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त योगदान दिया। अगर महाकुम्भ के कारण उत्पन्न आर्थिक कार्यकलाप को देखें तो ट्रांसपोर्ट, होटल, रेहड़ी-ठेला, रेस्टोरेंट, शॉपिंग इत्यादि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी है। पानी की बोतल 20 की जगह 30 रुपये की मिल रही थी। बताया जा रहा है कि बाइक वाले एक ट्रिप में 500 रुपये एवं नौका वाले 5000 से 10000 रुपये कमा रहे थे। महाकुम्भ के श्रद्धालु फिर काशी एवं अयोध्या जी भी जा रहे थे। बहुत से लेन-देन कैश हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, माथे पर तिलक, दान-दक्षिणा, दातुन, रुद्राक्ष, फूल-माला, पूजा सामग्री, बाइक, नौका इत्यादि का अधिकतर ₹भुगतान₹ कैश में हो रहा है।जब फाइनल आंकड़े निकाले जाएंगे, तो संभव है कि भारत की जीडीपी में इस महाकुम्भ का आर्थिक योगदान कहीं अधिक निकलेगा। कारण यह है कि जब कोई श्रद्धालु सुदूर प्रान्त से महाकुम्भ के लिए निकलता है, तो वह उसी समय से व्यय करना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर, महाकुम्भ के कारण प्रयागराज, काशी एवं अयोध्या में मंहगाई भारत की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। और अब ऐसे में देश की जीडीपी बढ़ेगी और पर व्यक्ति आय भी बढ़ा है । यूपी का अद्वितीय विकास कर मुख्यमंत्री योगी ने खुद को परफेक्ट साबित किया है और बटोगे तो कटोगे जैसे कालजई नारे ने तो उन्हे ब्रांड बना दिया । अब हिंदुत्व का परफेक्ट चेहरा बन चुके योगी को पीएम बनाए जाने से भाजपा पुनः अगले पंद्रह साल तक सुरक्षित हो जायेगी ।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

अधिसंख्य आबादी तक पहुंचें सस्ती दवाइयां

पिछले काफी समय से जेनेरिक या ब्रांडेड दवाओं पर बहस छिड़ी है। पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नियम लागू किया था। इसमें कहा गया था कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं भी लिखनी होंगी। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनएमसी के इस फैसले के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस नियम पर सवाल खड़े किए थे। कई डॉक्टर एसोसिएशन ने भी नए कानून का विरोध कर इसको वापस लेने की मांग की थी। तर्क यह दिया गया था कि ब्रांडेड दवा न लिखने से मरीजों को नुकसान हो सकता है। विरोध के बाद एनएमसी ने अपना फैसला वापस ले लिया था। सरकार मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवा लिखनी होंगी, न कि किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की। इसके बाद भी मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने लगेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जेनेरिक दवाओं के चलन से बड़ी फार्मा कंपनियों को सीधे नुकसान होगा। आमतौर पर सभी दवाओं में एक तरह का ह्यकेमिकल सॉल्टह्ल होता हैं। इन्हें शोध के बाद अलग-अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है, उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासिटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं, जब इसे किसी ब्रांड (जैसे क्रोसिन) के नाम से बेचा जाता है तो यह उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है।

जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। दरअसल, फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों की रिसर्च, पेटेंट और विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च करती हैं। जबकि जेनेरिक दवाइयों की कीमत सरकार तय करती है और इसके प्रचार-प्रसार पर ज्यादा खर्च भी नहीं होता। कई जानलेवा बीमारियां जैसे एचआईवी, लंग कैंसर, लीवर कैंसर में काम आने वाली दवाओं के ज्यादातर पेटेंट बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास हैं। वे इन्हें अलग-अलग ब्रांड से बेचती हैं। अगर यही दवा जेनेरिक में उपलब्ध हो तो इलाज पर खर्च 200 गुना तक घट सकता है। जैसे एचआईवी की दवा टेनोफिविर या एफाविरेज की ब्रांडेड दवा का खर्च 2,500 डॉलर यानी करीब 1 लाख 75 हजार रुपये है, जबकि जेनेरिक दवा में यही खर्च 12 डॉलर यानी महज 840 रुपये महीने तक हो सकता है। हालांकि, इन बीमारियों का इलाज ज्यादातर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में होता है। ऐसे में ये दवाएं इन अस्पतालों में या वहां के केमिस्ट के पास ही मिल पाती हैं।

देश में फार्मा इंडस्ट्री 1.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की है और इसकी सालाना ग्रोथ 11 प्रतिशत है। देश में सालाना करीब 1.27 लाख करोड़ की दवाएं बेची जाती हैं, इसमें 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है। भारत जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनियाभर की डिमांड की 20 प्रतिशत दवाइयां भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में 40 प्रतिशत और यूके में 25 प्रतिशत दवाइयां भारत सप्लाई करता है। 2018-19 में देश से 1,920 करोड़ डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की गईं। दुनियाभर में कुल वैक्सीन डिमांड का 50 प्रतिशत भारत से सप्लाई होता है। इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और जर्मनी में भी भारतीय दवाएं एक्सपोर्ट की गईं।

एक अनुमान के मुताबिक, किसी भी मरीज के इलाज के दौरान होने वाले खर्च का 70 प्रतिशत अकेले दवाओं पर खर्च हो जाता है। सरकार ने पिछले महीने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। फिलहाल सरकार की आयुष्मान भारत योजना से निःशुल्क इलाज और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाओं का मिलना लोगों के लिए राहत की बात है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा देश की अधिसंख्य आबादी तक बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य लोगों को ब्रांडेड महंगी दवाइयों के स्थान पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां

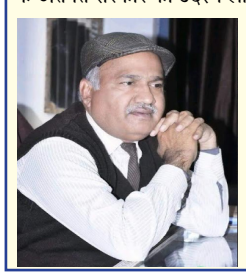

प्रदान करना है। सरकार के प्रयास के बावजूद अभी भी देश में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। समय आ गया है कि सामुदायिक स्तर पर जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। देश में बढ़ती महंगाई के दौर में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक दवाइयों के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। ऐसे में समय आ गया है कि सभी को जेनेरिक दवाओं के माध्यम से सस्ती दवाएं मुहैया कराइ जाएं।

विजय गर्ग
मलोट

क्यों क्रूर बदमाशी का रूप ले रही है रैगिंग?

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में कई वर्षों से, रैगिंग एक गंभीर प्रकार की बदमाशी और उत्पीड़न की समस्या रही है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर मनोवैज्ञानिक आघात, आत्महत्या और यहाँ तक कि हत्या जैसे हिंसक अपराध भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और 2009 से यूजीसी के एंटी-रैगिंग नियमों के बावजूद घटनाएँ जारी हैं। 2012 और 2023 के बीच रैगिंग के परिणामस्वरूप 78 छात्रों की मृत्यु से प्रवर्तन में विफलता उजागर हुई। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में, रैगिंग मुख्य रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के कारण होती है। भारतीय सामाजिक संरचनाओं द्वारा सुदृढ़ कठोर पदानुक्रम में वरिष्ठ छात्र कनिष्ठों पर अपना प्रभुत्व जताते हैं। यह इंजीनियरिंग कॉलेजों में शक्ति-आधारित सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करता है जब वरिष्ठ जूनियर से अपमानजनक कार्य करवाते हैं। आक्रामकता का महिमामंडन करने वाली अति-पुरुषवादी संस्कृति छात्रों को रैगिंग की परंपराओं का पालन करने के लिए मजबूर करती है। मेडिकल स्कूलों में छात्रों को ₹लचीलापन बनाने₹ के नाम पर धीरज-आधारित असाइनमेंट पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई उच्च शिक्षा संस्थान अत्यधिक हिंसा होने तक हस्तक्षेप को हतोत्साहित करते हैं क्योंकि वे रैगिंग को एक दीक्षा अनुष्ठान के रूप में देखते हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय (2023) में रैगिंग को ₹बॉन्डिंग प्रक्रिया₹ के रूप में लिखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक छात्र की असामयिक मृत्यु हो गई। प्रतिशोध का डर, प्रभावी गवाह सुरक्षा की कमी और सामाजिक कलंक पीड़ितों को रैगिंग की रिपोर्ट करने से अनिच्छुक बनाते हैं। 2009 में, अमन काचरू ने पहले शिकायत दर्ज नहीं की क्योंकि वह वरिष्ठ प्रतिशोध से डरता था, भले ही उसके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया हो। साथियों का दबाव या इसके बारे में संदेह कई छात्रों को रैगिंग की रिपोर्ट करने से रोकता है।

रैगिंग को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए सख्त और त्वरित दंड आवश्यक है। संभावित रैगर्स को हतोत्साहित करने के लिए, सुनिश्चित करें कि तत्काल अनुशासनात्मक उपाय किए जाएँ, जैसे निष्कासन, कानूनी मुकदमा और अपराधी को ब्लैकलिस्ट करना। कठोर समाधान समयसीमा और खुली निगरानी के साथ एक निजी ऑनलाइन शिकायत पोर्टल स्थापित करें। पारदर्शी जवाबदेही के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेल्पलाइन का एक नया संस्करण आवश्यक है क्योंकि वर्तमान हेल्पलाइन पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देती है। अनिवार्य कार्यशालाओं, संवेदनशीलता अभियानों और मेंटरशिप कार्यक्रमों को लागू करके सकारात्मक वरिष्ठ-जूनियर सम्बंधों को

प्रोत्साहित करें और दृष्टिकोण बदलें। एम्स दिल्ली रैगिंग के मामलों को कम करता है और नए छात्रों को परामर्श सत्र देकर एक सहायक संस्कृति को बढ़ावा देता है। संभावित मुद्दों को अधिक गंभीर होने से पहले पहचानने के लिए व्यवहार ट्रैकिंग, सरप्राइज चेक और छात्रावासों में सीसीटीवी गाने का उपयोग करें। आईआईटी मद्रास ने बातचीत की निगरानी के लिए सीसीटीवी और छात्र प्रोफाइलिंग का उपयोग करके रैगिंग की घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी की है। एक संगठित मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करें जहाँ वरिष्ठ नए कर्मचारियों की सकारात्मक तरीके से मदद करने के लिए नेतृत्व प्रमाणपत्र या अकादमिक क्रेडिट प्राप्त कर सकें। वरिष्ठ छात्र बिट्स पिलानी के ₹बडी सिस्टम₹ के माध्यम से जूनियर का मार्गदर्शन करते हैं, जो बदमाशी के बजाय रचनात्मक सम्बंधों को बढ़ावा देता है। नए छात्रों के लिए सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण वातावरण की गारंटी देने के लिए व्यवहार सम्बंधी आकलन को उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रणालियों में शामिल किया जाना चाहिए। सक्रिय अवलोकन संभावित खतरों के बारे में जानकारी प्रकट कर सकता है। संगठित सलाह कार्यक्रमों का समर्थन उपचार में सहायता कर सकता है।

रैगिंग की समस्या का कोई एकल, सार्वभौमिक रूप से लागू समाधान नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना महत्त्वपूर्ण है। रैगिंग को खत्म करने के लिए, एक बहुआयामी रणनीति, कठोर कानूनी प्रवर्तन, गुमनाम रिपोर्टिंग प्रणाली और त्वरित दंडात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है। मजबूत सलाह नेटवर्क, आवश्यक संवेदीकरण कार्यक्रम और दयालु सहकर्मी बातचीत को प्रोत्साहित करना निरोध के अलावा अन्य तरीकों से परिसर की संस्कृति को बदल सकता है। संस्थागत जवाबदेही और प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी यह गारंटी देगी कि उच्च शिक्षा संस्थान भय के बजाय सुरक्षा, समावेशिता और समग्र विकास के स्थान हैं। यूजीसी को उन संस्थानों के खिलाफ खंड 9.4 का उपयोग करना चाहिए जो अनुपालन नहीं करते हैं। अपराधियों को कड़ी सजा मिले, इसकी गारंटी के लिए फास्ट-ट्रैक ट्रायल और पुलिस सत्यापन जरूरी है। छात्रावासों में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए जो एआई-आधारित चेहरे की पहचान का उपयोग करते हैं। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए, एक डिजिटल आईडी-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परामर्श और एंटी-रैगिंग कार्यशालाओं को लागू करना अनिवार्य होना चाहिए। छात्र मेंटरशिप कार्यक्रमों द्वारा एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यूजीसी हेल्पलाइन की प्रतिक्रिया समय और पहुँच में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे डिजिटल शिकायत पोर्टल होने चाहिए जो गुमनाम हों और सीधे पुलिस अलर्ट प्रदान करें। सख्त कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अभी भी रैगिंग से ग्रस्त है। कानूनी कार्रवाई, संस्थागत सुधार, प्रौद्योगिकी एकीकरण और सांस्कृतिक परिवर्तन सभी एक बहुआयामी रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

-प्रियंका सौरभ

घूँघट की बगावत

2 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

लोक सभा में 22 जुलाई 2019 को दी गयी जानकारी में बताया गया था कि 2014 से 2019 के पांच साल के अंतराल में 1.09 करोड़ पेड़ काटने की अनुमति दी गई सबसे ज्यादा अनुमति 2018 19 में 2691028 पेड़ काटने की दी गई। यह संख्या तो अनुमति लेकर काटे गए पेड़ों की है। मानना है कि इससे भी कई गुना पेड़ प्रति वर्ष बिना अनुमति लिए कट जाते हैं। 13 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किए गए एक लिखित जवाब के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच देश भर में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जितने पौधे लगाए गए थे, उसमें से 4.84 करोड़ पौधे मर गए। दावा किया गया कि इन पांच वर्षों में कुल 20.81 करोड़ पौधे लगाए गए। इसमें से 15.96 करोड़ पौधों को ही बचाया जा सका है। इस आधार पर यदि राष्ट्रीय औसत देखें तो प्रतिपूरक वनीकरण के तहत वन कटाई के बदले जितने पौधे लगाए जा रहे हैं, उसमे से 24 फीसदी पौधे तमाम कारणों से खत्म हो जाते हैं।

पेड़ काटने पर जुर्माना व सजा की दरकार

भाजपा सरकार आने के बाद देश में नेशनल हाई-वे और एक्सप्रेस वे का निर्माण बड़ी तेजी के साथ शुरू हुआ। यह कार्य अनवरत जारी है। 2014-15 में जब केद्र में भाजपा की सरकार बनी तो देश में कल 97,830 किमी लबे राष्टय राजमार्ग थे। मार्च 2023 तक देश भर में अलग अलग 145, 155 किमी लबे राजमार्ग हो चुके थे। राजमार्ग के साथ ही तेजी से जगह जगह स्टेट हाई वे और जिला मार्ग भी बन रहे हैं। इन मार्ग के बनाने के लिए भारी संख्या में सड़क के किनारे के पेड़ कट रहे हैं। कटने वालों पेड़ के मुकाबले लगने वाले वृक्षों की संख्या कम है। सरकारी आंकड़े है कि लगने वाले वृक्षों में लगभग 24 प्रतिशत मर जाते हैं। ऐसे में आज जरूरत है कि किसी भी तरह का मार्ग बनाया जाए उसके किनारे के बड़े और पुराने पेड़ न काटें जाए। उन्हें दुसरी जगह शिप्ट कर दिया जाए या ऐसा रास्ता ही बनाया जाये जिससे पेड़ भी सलामत रहे और हाईवे भी बन जाये। लोक सभा में 22 जुलाई 2019 को दी गयी जानकारी में बताया गया था कि 2014 से 2019 के पांच साल के अंतराल में 1.09 करोड़ पेड़ काटने की अनुमति दी गई सबसे ज्यादा अनुमति 2018 19 में 2691028 पेड़ काटने की दी गई। यह संख्या तो अनुमति लेकर काटे गए पेड़ों की है। मानना है कि इससे भी कई गुना पेड़ प्रति वर्ष बिना अनुमति लिए कट जाते हैं। 13 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किए गए एक लिखित जवाब के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 के बीच देश भर में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जितने पौधे लगाए गए थे, उसमें से 4.84 करोड़ पौधे मर गए। दावा किया गया कि इन पांच वर्षों में कुल 20.81 करोड़ पौधे लगाए गए। इसमें से 15.96 करोड़ पौधों को ही बचाया जा सका है। इस आधार पर यदि राष्ट्रीय औसत देखें तो प्रतिपूरक वनीकरण के तहत वन कटाई के बदले जितने पौधे लगाए जा रहे हैं, उसमे से 24 फीसदी पौधे तमाम कारणों से खत्म हो जाते हैं। एक पेड़ की कीमत जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी एक पेड़ की कीमत 74 हजार 500 रुपये प्रति सालाना हो सकती है । हर हर साल बीतने के साथ ही उसकी कीमत में ये राशि जुड़ जाती है इस एक पेड़ की कीमत से हम अनुमान लाग सकते है कि प्रतिवर्ष लाखों पेड़ काट कर देश की कितनी बड़ी संपदा का हम दोहन कर रहे हैं। वनों का तेजी के साथ दोहन होने से पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जलवायु बदल रही है।

सांसों पर सकट बढ़ रहा है। प्रदुषण बढ़ने के कारण आक्सीजन मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। इसी से महानगरों से आदमी की आम आयु कम हो रही है. इसीलिए आज जरूरी हो गया है कि विकास के लिए पेड़ों को न काटा जाए इन पेड़ों को काटने की जगह यदि इन्हें दूसरी खाली जगह पर ले जाकर लगाया जाए तो समस्या का निदान हो सकता है। कुछ जगह पर यह कार्य हुआ भी है।

गाजियाबाद-दिल्ली ऐलिवेटेड रोड को बनाते समय 64 पेड़ उठाकर दूसरी जगह लगाए गए। उत्तरांचल में भी कई साल पहले यह कार्य हुआ। पेड़ का लगाना बहुत सरल है। उसे देख-रेख करना बड़ा करना बहुत ही कठिन है। पेड़ों के दोहन में सरकारी नीति भी जिम्मेदार है। नियम है कि पेड़ के काटने के आवेदन के साथ -साथ यह वायदा कराया जाता है कि आज कटे एक पेड़ की जगह दो पेड़ लगाएंगे। प्रति पेड़ काटने के लिए वन विभाग को दो सौ रुपया प्रति पेड़ सुरक्षा धन जमा करना होता है। पेड़ लगाकर वन अधिकारी को आप दिखा देंगे कि पेड़ लगा दिए तो सुरक्षा धन वापस हो जाएगा। आज के समय में दो सौ रुपए कोई मूल्य नहीं रखता। इसलिए कोई पेड़ लगाता नहीं। वन अधिकारी ये दो सौ रुपया सुरक्षा राशि जब्त कर लेते हैं। इस राशि से विभाग बरसात में वृक्षारोपण करता है। पेड़ लगवाने हैं तो हमें यह दो सौ की सुरक्षा राशि बढ़ाकर कम से कम पांच हजार करनी होगी। यह भी आदेश करना होगा कि दस साल से बड़े पेड़ कटेंगे नहीं। दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। एक बात और अवैध रुप से पेड़ कटान का दंड पांच हजार रुपए है। न पकड़े गए तो कुछ भी नहीं। पकड़े जाने पर वन अधिकारी खेल कर लेते हैं। कटते सौ पेड़ हैं दिखाते दस है इसी तरह से कम पेड़ की अनुमति लेकर ज्यादा पेड़ काटे जाने का प्रायः चलन है।

किसान को जरूरत के लिए अपनी भूमि से वृक्ष काटने की अनुमति हो किंतु अवैध रूप से पेड़ काटने पर एक पेड़ पर कम से कम 50 हजार रुपया जुमार्ना और छह माह की सजा का प्राविधान होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा पेड़ तो सरकारी योजनाएं कटवाती हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे जानकार बताते है कि पौधारोपण के नाम पर आमतौर पर सजावटी और विदेशी पौधे रोप दिए जाते हैं जो कम समय में बड़ा आकार ले लेते हैं लेकिन वे किसी भी दृष्टि से पर्यावरण के लिए लाभकारी नहीं होते। इस बात की निगरानी होनी चाहिए पेड़ फलदार हों या परम्परागत भारतीय पेड़ लगे। पीपल, वटवक्ष, नीम, पिलखन, साल, शीशम जामुन और आम जैसे वृक्ष प्रमुखता से लगाए जाएं।

विकास के नाम पर वृक्षों का संहार

मनुष्य विभिन्न खोजों के माध्यम से प्रकृति को अपने काबू में लाने का प्रयत्न कर रहा है वह प्रकृति से छेड़-छाड़ करके उसे नष्ट करने का काम उस पर विजय पाने में लगा हुआ है, लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास के बावजूद अभी तक हम बहुत से रहस्यों से अनजान हैं और उनकी खोज में लगे हुए हैं। चांद पर मनुष्य पहुंच गया, सूरज के बारे में ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त कर रहा है, वह सूरज को छू लेना चाहता है। चांद पर कदम रखकर वहां बस्तियां बसाना चाहता है। अंतरिक्ष में स्टेशन बनाकर वहां अनुसंधान कर रहा है। अब हम एआई के माध्यम से अपनी ही मशीन को अपने से ज्यादा बुद्धिमता वाला बना रहे हैं। जिससे वह मानव जाति से आगे के बारे में सोचने समझने और करने का काम करें लेकिन अंततः हमें प्रकृति के आगे हार मान लेनी पड़ती है।

विकास के नाम पर वृक्षों का संहार वन क्षेत्र और वृक्षों को नुकसान पहुंचाने का काम न सिर्फ निजी तौर पर हो रहा है बल्कि इसका सरकारी तौर पर भी विकास के नाम पर जिस तरह से वृक्षों का संहार किया जा रहा है और उसका आधार यह लिया जाता है कि इसके एवज में वृक्षारोपण कराना जरूरी होगा। लेकिन वृक्ष जहां लगे है उनको एक पौधे से वृक्ष बनने की लम्बी प्रक्रिया है और जब हम किसी बड़े पेड़ को काटते हैं और उसके बदले में वृक्षारोपण करते हैं तो एक तो उन जगहों पर यह सम्भव नहीं होता है। दूसरे उसके एवज में लगाये गए पेड़ का कटे हुए पेड़ जैसा होने में कई वर्ष लग जायेंगे। इस बात का ध्यान कभी भी विकास के नाम पर सरकारें और उनकी एजेन्सियां नहीं करती हैं। विकास की प्रक्रिया सस्टेबिल डेवलपमेंट से जुड़ी होनी चाहिए। विनाश करके विकास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यदि जंगल नहीं होंगे, शेर नहीं होंगे तो परिस्थितिकी तंत्र बदल जायेगा जिसका प्रभाव सीधे हमारे जीवन पर पड़ेगा। पृथ्वी जिस प्रकार गरम हो रही है उसी का प्रभाव है कि जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। जिसकी वजह से अचानक तूफान अत्यधिक गर्मी सर्दी, बरसात से जूझना पड़ रहा है। इससे हमारी फसलों का चक्र प्रभावित हो रहा है। उनकी पैदावार प्रभावित हो रही है। जिसके कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ को मिलेट वर्ष घोषित करना पड़ा।

यानी जब मौसम का दुष्प्रभाव रहेगा तो उसमें मोटे अनाज की पैदावार हो सकेगी। हम कार्बन उत्सर्जन लगातार किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के पानी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के कई शहर डूब जायेंगे। मुख्यमंत्री ने जिस प्रलय की बात की है वह प्रकृति का प्रकोप कही जा सकता है जिसके बारे में हम पहले नहीं सोचते हैं लेकिन जब यह सामने आ जाता है तब हम चिंता करते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम प्रलय की प्रतीक्षा न करके अपने पर्यावरण को हरा-भरा बनायें। उन्होंने इसे आस्था से जोड़ने पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन के कारकों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इसके निवारण का उपाय करना होगा। जहां तक पूरे पर्यावरण को हरा-भरा बनाने का प्रश्न है, वृक्ष हो एक ऐसी अनूठी चीज इस धरती पर है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। आपको हीरा मोती खनिज पदार्थ सब कुछ मिल जायेगा लेकिन वृक्ष सिर्फ इस पृथ्वी पर ही मिलेंगे। जिनका योगदान हमारे पर्यावरण को सही रखने के साथ ही हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में प्रयोग आते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य हैं लेकिन दुःखद यह है कि हम इसका मूल्य नहीं समझ रहे हैं जिसके कारण धड़ल्ले से वन क्षेत्र का नुकसान करके उसे अपने उपयोग में ला रहे है। इसके कारण हमारी चक्रीय साइकिल प्रभावित हो रही है। जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है जंगल उसके शिकार हुए हैं। इनकी वजह से वन्यजीवों का आबादी में प्रवेश और हमले बढ गए है। बहुत सी वन्य प्रजातियां इन्सान के लिए खतरा बन गई हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण के 2023 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 559.19 वर्ग किलोमीटर हरियाली क्षेत्र बहा है। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से उत्तर प्रदेश का वनाच्छदित क्षेत्र कम हो गया है। वैसे तो योगी सरकार के कार्यकाल के सात वर्षों में आंकड़ों का देखा जाये तो इस अवधि में 210 करोड पौधे लगाए गए हैं। सरकार ने इसके लिए पौधारोपण को प्रोत्साहित करने को काम किया हैं यह कितना फलीभूत हो रहा है यह आगामी वर्षों में दिखाई पड़ने लगेगा जहां तक आस्था का प्रश्न है, वन विभाग के प्रतिबंधों के कारण पहल भी पीपल, नीम बरगद आम जैसे पेड़ नहीं काटे जाते थे क्योंकि इसे धार्मिक और आस्था के साथ उसी प्रकार से जोड़ दिया गया था जिस प्रकार नदियों का गंदा न करना, सूर्य की उपासना करना, अग्नि को देवती मानना आदि-आदि। क्योंकि सारी सभ्यताएं और बसावट नदियों या जल स्रोत के किनारे ही अस्तित्व में आई हैं मानव सूर्य चन्द्रमा अग्नि को चमत्कार के रूप में देखता रहा, यही कारण है कि ऐसे सभी चमत्कारों की वह पूजा करने लगा। विज्ञान के निकास और जानकारी के स्रोत घटने के बावजूद वह सब कुछ जानते समझते हुए भी आस्था और धार्मिक स्वरूप मानकर पूजा कर रहा है।

मनुष्य विभिन्न खोजों के माध्यम से प्रकृति को अपने काबू में लाने का प्रयत्न कर रहा है वह प्रकृति से छेड़-छाड़ करके उसे नष्ट करने का काम उस पर विजय पाने में लगा हुआ है, लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास के बावजूद अभी तक हम बहुत से रहस्यों से अनजान हैं और उनकी खोज में लगे हुए हैं। चांद पर मनुष्य पहुंच गया, सूरज के बारे में ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त कर रहा है, वह सूरज को छू लेना चाहता है। चांद पर कदम रखकर वहां बस्तियां बसाना चाहता है। अंतरिक्ष में स्टेशन बनाकर वहां अनुसंधान कर रहा है। अब हम एआई के माध्यम से अपनी ही मशीन को अपने से ज्यादा बुद्धिमता वाला बना रहे हैं। जिससे वह मानव जाति से आगे के बारे में सोचने समझने और करने का काम करें लेकिन अंततः हमें प्रकृति के आगे हार मान लेनी पड़ती है। एक सुनामीं, एक भूकम्प, एक एस्टेरायड सब कुछ तहस-नहस कर सकता है। इसलिए हमें प्रकृति के प्रकोपों से बचाव के रास्ते तो ढूंढने चाहिए लेकिन विकास के नाम पर विनाश को दावत नहीं देनी चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश कैसे हुआ यह आज तक रहस्य ही है। यह सभ्यता आर्यों की थी या द्रविड़ों की यह भी नहीं जाना जा सका है। यदि पर्यावरण जीवन के अनुकूल रहेगा तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। इसलिए न सिर्फ आमजन को बल्कि सरकार को भी अपने विकास मॉडल में परिवर्तन करना चाहिए और विनाश करके विकास करने से दूर रहना चाहिए। यही मानवता के हक में होगा।

कामन सिविल कोड लागू करने का उपयुक्त समय नहीं ....

संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया तथा कहा कि उत्तराधिकार व विवाह के कानून में भी राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल ला के नाम पर शरीयत के नाम पर इस पर रोक नहीं लगना चाहिए। पर अम्बेडकर ने भी अन्त में माना कि इसे लागू करने का समय अभी नहीं आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 44) में केवल यही सुझाव है कि राज्य देश के नागरिकों के लिए एक व्यवहार संहिता के निर्माण का प्रयास करेगा। वह ऐसे नहीं कहा कि संहिता के निर्माण के पश्चात उसे सब नागरिकों पर इसी आधार पर लागू कर देगा कि वे नागरिक हैं।

उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता प्रदेश की 2.9 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति की आबादी पर लागू नहीं होगी। पहला प्रश्न तो यही है कि जो संहिता (कोड) उत्तरप्रदेश की 2.9 प्रतिशत आबादी पर लागू नहीं होगी तो वह समान नागरिक संहिता कैसे हुई ? अनुसूचितजाति लागू न होने / करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि- अभी वह बहुत पिछड़े हैं उनमें शिक्षा का प्रतिशत कम है। उनमें जागरूकता की कमी है। जब तक वे समाज के अन्य वर्गों के आस-पास शिक्षा व जागरुकता की दृष्टि से संपन्न नहीं हो जाते तब तक उनपर समान नागरिक संहिता कैसे लागू कर सकते हैं। मुस्लिम आबादी तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की आबादी से भी कम है फिर समान नागरिक संहिता लागू करने की इतनी जल्दी क्यों? वास्तव में उत्तराखंड की भाजपा सरकार का लक्ष्य समान नागरिक संहिता लागू करना नहीं बल्कि इस बहाने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है और अपनी हिन्दुत्व की छवि को और चमकदार बनाना है। भारत में आदिवासियों की (अनुसूचित जनजाति) आबादी कुल जनसंख्या 8.6 प्रतिशत है। कुछ राज्यों में तो वे बड़ी संख्या में है। अरुणाचल प्रदेश में 68.8, मिजोरम में 94.4. नागालैंड में 86.5. मेघालय में 86.1 लक्ष्य द्वीप में 94.8, त्रिपुरा में 31.8, सिक्किम में 33. 8. छत्तीसगढ़ में 30.6, झारखंड में 28, गुजरात में 14.8, मध्य प्रदेश में 211 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जन जाति की है। जो अभी भी परंपराओं में जकड़ी हुई है। संविधान निर्माता इस बात को मली भांति जानते थे। इसलिए संविधान बनाते समय अनेक प्रांतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसीलिए लिए अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाना भी आसान नहीं है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों की रुढिजन्य परंपराओं एवं संस्कृति को देखते हुए उनकी रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं। एक देश एक कानून सर्वत्र नहीं लागू होता उसके अपवाद भी हैं। जो लोग जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद-370 (जो अब समाप्त हो चुका है) में विशेष प्रावधानों के लिए रात दिन छाती पीटते थे और एक देश एक विधान का नारा देते हैं। उन्हें संविधान के अनुच्छेद-३७१ में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों पर एक शब्द भी नहीं बोला। संविधान के अनुच्छेद-371 (क) में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 (1) में कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी - (क) निम्नलिखित के संबंध में संसद कोई अधिनियम नागालैंड राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती अर्थात नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, नागा रुढिजन्य विधि और प्रक्रिया, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रुढिजन्य विधि के अनुसार होने हैं, भूमि और उसके संपत्ति के श्रोतों का स्वामित्व और अंतरण।

वर्तमान वर्ष के 27 जनवरी को उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसमें तीन तलाक, इद्दत हलाल जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। राज्य में अब सभी धर्मों के लिए बहु-विवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा बेटियों के पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। संहिता में सभी धर्मों के विवाह विरासत भरण पोषण और अन्य नागरिक मामलों के लिए समान नियमों की परिकल्पना की गई है। अब किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए अपने जीवनसाथी के जीवित रहने तक दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। तथा इसमें बच्चों को संपत्ति में समान हक मिलेगा। इसी तरह से मिजोरम राज्य के संबंध में अनुच्छेद, 371 (छः) में विशेष उपबंध है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं मिजो रुढिजन्य विधि प्रक्रिया, सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय मिजो रुढिजन्य विधि के अनुसार होने है। भूमि का स्वामित्व और अंतरण के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जबतक मिजोरम राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है। इसका अर्थ यह है कि- संसद द्वारा बनाए गए दीवानी और फौजदारी कानून स्वतः नागालैंड व मिजोरम पर नहीं लागू होंगे इसके अनुसार समान नागरिक संहिता आदि संसद बना भी देती है तो नागालैंड व मिजोरम पर लागू नहीं होगी जब तक उन राज्यों की विधान सभाएं उनका अनुमोदन न कर दें।

भारत में विद्यमान इसी विविधता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने तत्काल समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया। बल्कि नीति-निदेशक तत्वों में जो बाध्यकारी न होते के अनुच्छेद 44 में यह व्यवस्था कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। भारत के संविधान निमार्ता यह चाहते थे कि उचित अवसर आने पर समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) कानून का रूप ले। इसको वे देश की एकता की भावना को मजबूत करने के लिए जरूरी मानते थे। संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों में भी अधिकांश समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं थे पर वे मानते थे कि अभी इसका समय नहीं आया है। संविधान सभा के सदस्य हुसैन इमाम ने कहा कि भारत एक वृहद देश है इसकी भारी जनसंख्या इतनी विभिन्न है कि उस पर एक प्रकार का रंग चढ़ना असम्भव है। कहीं अधिक पिछड़े लोग हैं जो कहीं अधिक प्रगतिशील । इसलिए अभी हर क्षेत्र में एक कानून उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता बनाना सर्वथा उपयुक्त तथा अति वांछनीय है किन्तु बहुत समय पश्चात ऐसा करना चाहिए। इसके लिए हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जबकि सारा भारत शिक्षित हो जाय, जब लोग प्रगतिशील हो जायें जब उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाय, जब प्रत्येक मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होने लगे तथा अपना जीवन संग्राम स्वयं लड़ सके। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया तथा कहा कि उत्तराधिकार व विवाह के कानून में भी राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल ला के नाम पर शरीयत के नाम पर इस पर रोक नहीं लगना चाहिए। पर अम्बेडकर ने भी अन्त में माना कि इसे लागू करने का समय अभी नहीं आया है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 44) में केवल यही सुझाव है कि राज्य देश के नागरिकों के लिए एक व्यवहार संहिता के निर्माण का प्रयास करेगा। वह ऐसे नहीं कहा कि संहिता के निर्माण के पश्चात उसे सब नागरिकों पर इसी आधार पर लागू कर देगा कि वे नागरिक हैं। यह सर्वथा संभव है कि संसद आरम्भ करने के निमित्त ऐसा प्रावधान से बना दे जिससे यहां मेरे मित्रों ने जो आशंका प्रकट की है वह सर्वथा मिथ्या हो जाय। समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी है। पर इसे उपयुक्त समय पर लागू होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे के बाहर रखा जाता है (जैसा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने किया है) तो इसका अर्थ यह है कि अभी अनुसूचित जनजातियों पर कामन सिविल कोड लागू करने का उपयुक्त समय नहीं आया है। जो तर्क कामन सिविल कोड को अनुसूचित जनजातियों पर लागू न करने पर दिए जा रहे हैं क्या वे तर्क अल्पसंख्यक मुसलमानों पर नहीं लागू हो सकते? इसीलिए जब भाजपा व आर.एस.एस. के लोग समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करते हैं तो उनका उद्देश्य इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता मजबूत करना नहीं बल्कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा कर एकता को कमजोर करना है। इसलिए भाजपा सरकारें समान नागरिक संहिता को नेक इरादे से लागू करना चाहती है, इस पर विश्वास करना मुश्किल है।

घूँघट की बगावत

2 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

रुस को चीनी शिकंजे से दूर रखने में अमेरिका की भलाई

जबसे ट्रंप ने पूर्ववर्ती जो बाइडन प्रशासन की नीतियों को उलटकर पुतिन के साथ नरम रुख अपनाया है तो कुछ टिप्पणीकार इसकी तुलना 'रिवर्स निक्सन' यानी पिछली सदी के आठवें दशक में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के रणनीतिक उलटफेर से कर रहे हैं। निक्सन ने सोवियत संघ की काट के लिए माओवादी चीन से हाथ मिलाया था। इसने रूस-चीन कम्युनिस्ट गठबंधन में दरार डाली।

परिणामस्वरूप अमेरिका शीत युद्ध का विजेता बना। उसी तर्ज पर अब यह माना जा रहा है कि ट्रंप भी इसी प्रकार रूस से तनातनी घटाकर चीन के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता को दुर्बल करने की मंशा से अलग राह पर चल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस संदर्भ में कहा है, अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ युद्ध रोकने को प्राथमिकता दे रहा है, यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्रों में सैन्य संसाधन बनाए रखने से जुड़ी समस्या की वास्तविकता को भांप रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए यूरोप से कूच करना चाहता है कि एशिया में चीन का प्रतिरोध विफल न हो जाए।

इसका अर्थ है कि रूस के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाकर, यूक्रेन युद्ध का अंत कराकर और यूरोप की सुरक्षा का भार यूरोपीय देशों के हाथों सौंप कर अमेरिका अपनी सैन्य और सामरिक ऊर्जा को हिंद-प्रशांत में चीन के विरुद्ध केंद्रित करने का प्रयास करेगा। इससे पहले बाइडन प्रशासन ने भी चीन को अमेरिका का मुख्य प्रतिद्वंद्वी करार दिया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका यूरोप के सुरक्षा मामलों में उलझ गया और एशिया में चीन का डटकर मुकाबला नहीं कर पाया। जहां तक यूक्रेन युद्ध की बात है तो इसने चीन को लाभ पहुंचाया है। इसके चलते रूस पर पश्चिमी देशों का आर्थिक प्रतिबंध और दबाव बढ़ा, जिससे रूस चीन पर अत्यधिक निर्भर होता गया। इसी स्थिति में मास्को और बीजिंग ने 'असीमित मित्रता' का एलान किया था। 'नए शीत युद्ध' के अंतर्गत चीन और रूस सशक्त संयुक्त मोर्चा बनाकर अमेरिका का मुकाबला करने लगे थे और इससे चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षा और मनोबल को नए पंखे लगे।

यूक्रेन युद्ध का दूसरा फायदा चीन को इस प्रकार मिला कि अमेरिका का ध्यान यूरोप में मित्र-राष्ट्रों की ओर केंद्रित हो गया। इससे एशिया में चीन के विस्तारवाद से भयभीत अमेरिकी साथियों को पर्याप्त सामग्री और सहायता नहीं पहुंच रही थी। वैसे तो अटलांटिक और प्रशांत क्षेत्रों की रक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, परंतु अमेरिका द्वारा रूस को खतरनाक दुश्मन करार देने से चीन को एशिया में मनमानी करने की काफी ढील और सहूलियत मिल रही थी। रूस को चीनी शिकंजे से दूर रखना और चीन के साथ कड़ाई से जूझने में ही अमेरिका की भलाई है, लेकिन इस नीति को मूर्त रूप देना आसान नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है कि चीन का 'सौतेला बच्चा' या 'छोटा भाई' बनने में रूस को घाटा है, लेकिन उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में माना है कि रूस और चीन के बीच प्रगाढ़ आर्थिक संबंध हैं, जो एक-एक नहीं तोड़े जा सकते हैं।

अमेरिका रूस पर लागू सभी आर्थिक प्रतिबंध और तकनीकी पाबंदियां हटा भी दे और रूस की खनिज संपदा के विकास के लिए अनुबंध भी करे, तब भी पुतिन आशंकित हो सकते हैं कि ये स्थायी उपाय नहीं होंगे। कारण यही कि अगर चार वर्ष बांद ट्रंप के उत्तराधिकारी ने पश्चिमी उदारवादी विचारधारा को पुनजार्गृत किया और रूस पर नकेल कसने की नीति वापस अपनाई तो रूस को लेने के देने पड़ जाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ वर्षों से चली आ रही अनबन दूर करने और संबंध सुधारने के लिए कुछ अप्रत्याशित कदम उठाए हैं। इस-से वैश्विक भूराजनीतिक परिदृश्य पर बड़ी हलचल हुई है। उनकी ऐसी असामान्य सी पहल ने नाटो गठबंधन के भीतर ही दरारें पैदा कर दी हैं। इससे पश्चिमी देश इस बात को लेकर आशंकित हुए हैं कि अमेरिका यूक्रेन और यूरोप की रक्षा के प्रति अपेक्षित दायित्व निभाने का इच्छुक नहीं रह गया है।

ट्रंप द्वारा यूरोप को एक तरह से दरकिनार करने और उदारवादियों के सबसे अधिक निशाने पर रहने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मेल-मिलाप से यूरोपीय देशों में निराशा का माहौल है। ट्रंप के रुख-रवैये में आए इस बदलाव से दूसरा परेशान पक्ष है चीन। यूक्रेन के अस्तित्व और रूस के साथ उसके तीन वर्षों से चल रहे युद्ध के अंजाम जैसे विषय विश्व व्यवस्था के लिए अहम तो हैं, पर इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका रूस को चीन के चंगुल से निकालकर बाहर लाने में कामयाब हो सकता है?

अतीत में निक्सन को अपनी नीति में सफलता इसीलिए भी मिली थी कि तब यूरोप भी अमेरिका से सहमत था। फिलहाल अमेरिका और यूरोप में मतभेद इतने गहरे हैं कि रूस पर भले ही अमेरिकी दबाव कम हो जाए, लेकिन यूरोप के साथ रूस के आर्थिक और तकनीकी रिश्ते कड़वे ही रहेंगे। विशेषकर तब तक जब तक कि यूरोप के अनुसार रूस यूक्रेन के साथ न्याय नहीं करता। वहीं, मास्को के नजरिये से बीजिंग कई मायनों में वाशिंगटन से विश्वसनीय और स्थिर लगता है। इसी कारण पुतिन ने दोहराया, ह्यचीन के साथ रूस के संबंध सामरिक हैं, ये क्षणिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होंगे और बाहरी कारकों से बाधित नहीं होंगे। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने भी कहा है, अंतरराष्ट्रीय स्थिति चाहे जैसे भी बदलती हो, चीन-रूस संबंध निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे।

तमाम अड़चनों के बावजूद अमेरिका अगर रूस के साथ रिश्ते सुधारेगा तो चीन पर रूस की निर्भरता थोड़ी कम होगी और रूस अमेरिका से कुछ अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने में भी संकोच नहीं करेगा। इस गतिशील अंतरराष्ट्रीय परिवेश में अंततः मौलिक परिवर्तन होगा या नहीं, यह तो समय ही बता सकता है। हम इतना जरूर मान सकते हैं कि रूस के प्रति ट्रंप के बदले रवैये से चीन चिंतित है और अगर अमेरिका-रूस संबंध बेहतर होंगे तो यह भारत के हित में भी होगा। यदि रूस चीन के दबदबे से उबरे तो भारत के लिए खुशखबरी होगी। यूक्रेन की अखंडता और सुरक्षा की फिक्र सबको है, लेकिन वैश्विक भूराजनीतिक दृष्टि से ट्रंप के नए दांव अवांछित नहीं हैं।

फसल विविधीकरण पर जोर

मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मोदी सरकार फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। इसके तहत सरकार ने दलहनी-तिलहनी फसलों और मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है। इससे इन उपजों की सरकारी खरीद में अपेक्षित सुधार आया है।

इसी को देखते हुए अब सरकार दलहनी-तिलहनी और मोटे अनाजों की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद-भंडारण-विपणन का देशव्यापी नेटवर्क बना रही है। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि अनाजों के केंद्रीकृत भंडारण पर होने वाला भारी भरकम खर्च भी घटेगा।

इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों में स्थानीय उपज को भंडारित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाएगा। विरोधी भले ही पीएम मोदी पर आरोप लगाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि आजादी के बाद वह पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बंजर होती जमीन की सुध ली।

विश्व की ढाई प्रतिशत जमीन पर दुनिया की 17.8 प्रतिशत जनसंख्या का पेट भरना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब तक देश के किसान इस चुनौती पर खरे उतरे हैं, लेकिन मिट्टी की उर्वरता में ह्रास की दर को देखें तो भविष्य की राह आसान नहीं है। बेजान होती मिट्टी का ही नतीजा है कि बुजुर्ग यह शिकायत करते रहते हैं कि आखिर अनाज इतने बेस्वाद कैसे होते जा रहे हैं?

पहले किसान एक साथ कई फसलें बोते थे और एक ही फसल की सैकड़ों किस्में मौजूद थी। दरअसल हरित क्रांति के दौर में क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी दशाओं की उपेक्षा कर फसलें ऊपर से थोपी गईं। जैसे दक्षिण भारत में गेहूं और पंजाब में धान की खेती। किसान उन्हीं फसलों की खेती करने लगे, जिनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता हो। इससे दलहनी, तिलहनी फसलें अनुर्वर और सीमांत भूमियों पर धकेल दी गईं।

इस प्रकार फसल चक्र थमा, जिससे मिट्टी की उर्वरता, नमी, भुरभुरेपन में कमी आनी शुरू हुई। इसकी भरपाई चके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा और हरी खाद, कंपोस्ट आदि भुला दिए गए। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से शुरू में तो उत्पादकता बढ़ी, लेकिन आगे चलकर उसमें गिरावट आने लगी। उदाहरण के लिए 1960 में एक किलो रासायनिक खाद डालने पर उपज में 25 किलो की बढ़ोतरी होती थी, जो कि 1975 में 15 किलो और 2014 में चार किलो ही रह गई।

मिट्टी के महत्व का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस मिट्टी की दो सेंटीमीटर मोटी परत बनने में 500 साल लग जाते हैं, वह महज कुछ ही सेकेंडों में नष्ट हो जाती है। अब तक देश की 9.60 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो चुकी है। हर साल 5.3 अरब टन मिट्टी की ऊपरी परत जल कटाव से नष्ट हो रही है।

दशकों की उपेक्षा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी की सेहत की सुध लेते हुए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में स्वस्थ धरा-खेत हरा थीम के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की। इस योजना के तहत साल में दो बार मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं अर्थात रबी और खरीफ फसल की कटाई के बाद या जब खेत में कोई फसल न लगी हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी में मौजूद 12 तत्वों की मात्रा दिखाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार होने के बाद कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि सखी आदि किसानों को सुझाव देते हैं कि किस मिट्टी में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाए। इससे रासायनिक उर्वरकों के अनावश्यक और असंतुलित इस्तेमाल में कमी आई है। गुजरात में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को मिली सफलता को देखते हुए ही प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया।

इस योजना के एक दशक पूरा होने तक देश में 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। देश भर में 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गईं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल सभी प्रमुख भाषाओं में कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के इस अनूठे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और एकलव्य माडल स्कूलों को शामिल किया गया है।

2024 तक 1,020 स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन स्कूलों में 1,000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का 2022-23 से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। सरकार ने जून 2023 में ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (वीएलएसटीएल) के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

वीएलएसटीएल की स्थापना ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों द्वारा की जा सकती है, जिसमें स्वयं सहायता समूह, स्कूल, कृषि विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। फरवरी 2025 तक 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। 2023 में सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) के साथ एकीकृत कर दिया, ताकि सभी परीक्षण परिणामों को मानचित्र पर देखा जा सके।

सरकार ने पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना भी शुरू की है। इसमें उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 21 उर्वरकों को एनबीएस योजना के दायरे में लाया जा चुका है।

गर्मी ने दिखाया तेवर

इस साल फरवरी के पहले ही हफ्ते में मैदानी राज्यों में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू दिए। ध्यान रहे कि बीता साल भारत के लिए बेहद गर्म रहा था, जिसमें हर महीने औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया था। इस वर्ष जिन दिनों में वसंत की मधुरता का अहसास होना चाहिए, उन दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि में पारा बढ़ गया और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ओ-डिशा, केरल और दमन-दीव के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 35-38 डिग्री के बीच रिकार्ड किया जा रहा है।

दिल्ली और उसके आसपास का तापमान 28 डिग्री से पार होना सामान्य नहीं। बीते कुछ वर्षों में जब गर्मी अचानक बढ़ती थी तो मान लिया जाता था कि यह अल नीनो या ला नीना का असर है, लेकिन इस बार तो ला नीना अप्रभावी रहा। स्पष्ट है कि मौसम का बदलता मिजाज जलवायु परिवर्तन की मजबूत होती पकड़ की तरफ इशारा कर रहा है।

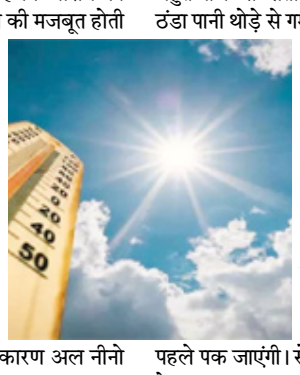

अंतरराष्ट्रीय मौसम संस्था कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार, इस साल जनवरी में विश्व का औसत तापमान 13.23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले साल की सबसे गर्म जनवरी से 0.09 डिग्री अधिक था। ऐसा तब हुआ, जब प्रशांत महासागर में ला नीना प्रभाव विकसित हुआ था। दक्षिणी अमेरिका से भारत तक के मौसम में बदलाव के सबसे बड़े कारण अल नीनो और ला नीना प्रभाव ही होते हैं।

अल नीनो का संबंध भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और सूखे से है, वहीं ला नीना अच्छे मानसून का वाहक है। इन दोनों घटनाओं का संबंध सुदूर पेरू के तट (पूर्वी प्रशांत) और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट (पश्चिमी प्रशांत) से है। हवा की गति इन प्रभावों को दूर तक ले जाती है। यहां जानना जरूरी है कि भूमध्य रेखा पर समुद्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।

इस इलाके में पूरे 12 घंटे निर्बाध सूर्य के दर्शन होते हैं, जिससे सूर्य की ऊष्मा अधिक समय तक यहां की धरती की सतह पर रहती है। तभी भूमध्य क्षेत्र या मध्य प्रशांत इलाके में अधिक गर्मी पड़ती है। इससे समुद्र की सतह का तापमान प्रभावित रहता है। आमतौर पर सामान्य परिस्थिति में भूमध्यीय हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और गर्म हो चुके समुद्री जल को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्री तट की ओर बहा ले जाती हैं।

गर्म पानी से भाप बनती है और उससे बादल बनते हैं। परिणामस्वरूप पूर्वी तट के आसपास अच्छी वर्षा होती है। नमी से लदी गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो उनकी नमी निकल जाती है और वे ठंडी हो जाती हैं। तब पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ठंडी हवाएं पेरू के समुद्री तट एवं उसके आसपास नीचे की ओर आती हैं। तभी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र से ऊपर उठती गर्म हवाएं इससे टकराती हैं। इससे निर्मित चक्रवात को वाकर चक्रवात कहते हैं।

अल नीनो परिस्थिति में पछुआ हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं एवं समुद्र का गर्म पानी लौट कर पेरू के तटों पर एकत्र हो जाता है। इस तरह समुद्र का जल स्तर 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप वाष्पीकरण होता है और बरसात वाले बादल निर्मित होते हैं। इससे पेरू में तो भारी बरसात होती है, लेकिन मानसूनी हवाओं पर इसके विपरीत प्रभाव के चलते ऑस्ट्रेलिया से भारत तक सूखे की स्थिति बन जाती है।

ला नीना प्रभाव के दौरान भूमध्य क्षेत्र में सामान्यतया पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने वाली अंधड़ हवाएं पेरू के समुद्री तट के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इससे पेरू के समुद्री तट पर पानी का स्तर बहुत नीचे आ जाता है, जिससे समुद्र की गहराई का ठंडा पानी थोड़े से गर्म पानी को प्रतिस्थापित कर देता है। इन दिनों ला नीना सक्रिय है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से न तो भारत में वर्षा हो रही है और न ही पहाड़ों पर पर्याप्त बर्फबारी।

उलटे तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम की गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो सबसे बड़ा नुकसान खेती-किसानी को होगा। गेहूं के दाने कमजोर होंगे और चना-सरसों फसल भी समय से पहले पक जाएंगी। सेब और लीची के पेड़ों में फूलों के परागण का समय कम रहेगा, जिससे फल बनने एवं पकने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। यदि तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो यह खरीफ मौसम के दौरान किसानों की आय 6.2 प्रतिशत तक घटा देता है और असिंचित क्षेत्रों में रबी मौसम के दौरान किसानों की आय छह प्रतिशत तक कम कर देता है।

इसी तरह बारिश में औसतन 100 मिमी की कमी होने पर खरीफ के मौसम में किसानों की आय में 15 प्रतिशत और रबी के मौसम में किसानों की आय में सात प्रतिशत की गिरावट आती है। अब यह खतरा सिर पर है। मच्छर जैसे परजीवी बढ़ते तापमान से पैदा हो रहे हैं। पारंपरिक दवाएं उन पर बेअसर साबित हो रही हैं। धरती पर नमी कम होने से गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग का खतरा भी बढ़ जाता है।

यदि गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो लू के दिन भी बढ़ेंगे, जो देश की बड़ी आबादी के स्वास्थ्य और आर्थिक हालात पर असर डालेंगे। ऐसे में सरकार को अपनी नीतियां गर्म होते मौसम के अनुरूप बनाने की जरूरत है। सबसे पहले ग्रीनहाउस गैस कम करने के तरीकों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। फिर ऊर्जा और पानी की बचत प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। अंत में इससे प्रभावित होने वाले मेहनतकश लोगों को राहत और वैकल्पिक आजीविका की कार्ययोजना गांव स्तर पर बनाई जानी चाहिए।

1990 के दशक में सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल आपमें से किसी ने अवश्य खेला होगा

माकपा की सोच बड़े राजनीति बदलाव की सूचक

जब तक कांग्रेस राजनीति की धुरी रही, विपक्षी खेमे के लिए गैर-कांग्रेसवाद बड़ा मुद्दा रहा। 1967 की बंगाल की सरकार रही हो या 1969 की पंजाब की सरकार, उनके गठन में सीपीएम और जनसंघ का साथ आना गैर कांग्रेसवाद का ही नतीजा था। हालांकि भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के बाद वामपंथी राजनीति के लिए गैर कांग्रेसवाद मुद्दा नहीं रहा, बल्कि कभी पर्दे के पीछे तो कभी सामने से कांग्रेस का साथ देने में वामपंथी राजनीति कहीं ज्यादा सहज रही।

वास्तव में वामपंथी राजनीति हमेशा से विरोधाभासी रही है। दुनिया की चुनी हुई पहली वामपंथी सरकार 1957 में केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद की अगुआई में बनी थी। इसे दो साल बाद ही नेहरूजी की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बावजूद पूरी वामपंथी राजनीति की वैचारिक यात्रा को देखेंगे तो वह नेहरू के कथित आदर्शवादी स्वप्न की ही प्रशंसक नजर आती है। इस प्रशंसा के बावजूद बंगाल, केरल और त्रिपुरा में वह कांग्रेस की ही सबसे प्रबल विरोधी रही।

बंगाल में माकपा के नेतृत्व में वाम दलों का 34 साल तक शासन रहा। त्रिपुरा में भी वाम दलों की सत्ता रही। केरल में लगातार दूसरी बार उनकी सरकार है। अतीत में केरल में कभी उनकी तो कभी कांग्रेस की अगुआई वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार रही है। यानी स्थानीय स्तर पर सीपीएम की राजनीति कांग्रेस विरोध पर ही केंद्रित रही है।

पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। अब सीपीएम की केरल इकाई का नोट एक तरह से कांग्रेस मुक्त नारे का केरल में विस्तार दिख रहा है। केरल में संघ ताकतवर है और वामपंथी उसके कट्टर विरोधी हैं। यह विरोध अक्सर खूनी रूप लेता रहा है। केरल में संघ समर्थित वोटरों का बड़ा समूह है।

वाम मोर्चे को हराने के लिए संघ समर्थित कई वोटर कांग्रेसी मोर्चे को वोट देते रहे। कांग्रेस को डर है कि विजयन के नए रुख से संघ समर्थक वोटरों में संशय बढ़ेगा और संभव है कि वे वामदलों को किसी भी कीमत पर हराने का विचार त्याग दें। इससे केरल की राजनीति बदल सकती है। सीपीएम के इस रुख से विपक्षी राजनीति भी बदल सकती है।

केरल में 2026 में विधानसभा का चुनाव है, जबकि बिहार में इसी साल है। बिहार के विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस भी है और वाम दल भी। केरल में माकपा के भाजपा समर्थक रुख का असर बिहार में भी पड़ सकता है। विजयन के बदले रुख के नैरेटिव का भाजपा प्रचार करेगी तो कांग्रेस गठबंधन की राजनीति

देश की वामपंथी राजनीति हरसंभव मंच से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सांप्रदायिक एवं समाज विरोधी बताने की मुनादी करती रही है। भाजपा के लिए वह फासीवादी विशेषण का भी इस्तेमाल करती रही है। अब लगता है कि उसका भाजपा को लेकर पुराना सोच बदलने लगा है।

में सीपीएम पर नए रुख को साफ करने का दबाव बना सकती है। इससे विपक्षी गठबंधन में गांठ बढ़ सकती है।

देश की वामपंथी राजनीति हरसंभव मंच से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सांप्रदायिक एवं समाज विरोधी बताने की मुनादी करती रही है। भाजपा के लिए वह फासीवादी विशेषण का भी इस्तेमाल करती रही है। अब लगता है कि उसका भाजपा को लेकर पुराना सोच बदलने लगा है।

वाम मोर्चे की प्रमुख घटक माकपा यानी सीपीएम की केरल इकाई ने मुख्यमंत्री पी. विजयन के नेतृत्व में अपने एक नोट में हाल में यह कहकर सबको चौंका दिया कि वह मोदी सरकार को फासीवादी या नियो फासिस्ट नहीं मानती। केरल से ही सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य आर. बालन भी खुलकर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी ने कभी भाजपा सरकार को फासीवादी नहीं कहा।

दिलचस्प यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए गठित विपक्षी मोर्चे आईएनडीआइए की एक धुरी वामपंथी धारा भी है। ऐसे में जब उसकी ही प्रमुख इकाई सीपीएम भाजपा को लेकर अपनी पुरानी राय बदलने लगे तो बहस होना स्वाभाविक है। केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रमेश चेन्निथला को सीपीएम के इस रुख से राज्य में कांग्रेस का भविष्य डगमगाता दिखने लगा है।

उन्होंने यह कहने में देर नहीं लगाई कि सीपीएम का यह नोट केरल के अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा समर्थक वोटरों का समर्थन हासिल करने की रणनीति है। सीपीआई यानी भाकपा ने भी माकपा के बदले सुर पर आपत्ति जताई है। इस सियासी तूफान के बीच केरल कांग्रेस के अहम नेता शशि थरूर भी बगावती मुद्रा में आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस का अधिक चिंतित होना स्वाभाविक है।

भाजपा को लेकर सीपीएम का ताजा रुख एक बड़े वर्ग को नागवार गुजर सकता है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राजीव गांधी विरोधी लहर के बाद बनी वीपी सिंह की संयुक्त मोर्चा की सरकार को भाजपा के साथ वाममोर्चे ने भी बाहरी समर्थन दिया था, जिसमें सीपीएम मुख्य घटक थी।

इससे पहले 1969 में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरनाम सिंह की अगुआई में चार दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाई थी। उसमें अकाली दल के 43, जनसंघ (अब भाजपा) के आठ, सीपीआई के चार और सीपीएम के दो सदस्यों के साथ दो निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। उस सरकार के उपमुख्यमंत्री जनसंघ नेता बलराम दास टंडन थे।

उसी सरकार में पंजाब की वामपंथी राजनीति के दिग्गज सतपाल डांग खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बने थे। पंजाब की तरह बंगाल के 1967 के चुनावों में भी कांग्रेस की पराजय हुई। तब बांग्ला कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और जनसंघ ने मिलकर सरकार बनाई थी, जिसके अगुआ बांग्ला कांग्रेस के अध्यक्ष अजय मुखर्जी थे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com